हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 7 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(6)28
वर्श 1979–80 का बजट पे ा करना	(6)47

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 7 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

Introducing lottery system of auctioning country vends

***1051. Ch. Har Swarup Bura:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state:-

(a) whether Government has suffered loss or gained profit by introducing lottery system of giving contract of country liquor vends in the State; and

(b) If loss suffered, whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the existing lottery system, if so, the details thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) देसी भाराब से राजस्व में कमी हुई है किन्तु यह सारी कमी भाराब की दुकानों के आवंटन के लिए लाटरी प्रणाली आरम्भ करने के कारण नहीं हुई हैं। राजस्व में हानि 1–4–1978 से मद्य निशेध के क्रमिक कार्यक्रम के क्रार्यान्वयन के फलस्वरूप हुई है।

(ख) अब सरकार ने 1979–80 वर्श के लिए नीलामी प्रणाली के उसी आधार को अपनाने का निर्णय किया है जो 1977–78 में प्रचलित थी।

चौधरी हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन पंचायतो ंके रैजोल्यू ान आ चुके हैं कि वहां पर भाराब का ठेका नहीं होना चाहिए, क्या उन रेजाल्यू ांज को ध्यान में रखते हुए लीकर वैंड्ज को बन्द करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी भोर सिंहः इस सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि जो पंचायतें रेजोल्यू ान पास करके भेजती हे, उसके मुताबिक वहां पर दुकानें बन्द कर दी जाती है लेकिन इससे पहले कि बन्द करें, डिस्ट्रिक्ट आफिसर से रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि वहां पर नाजायज भाराब तो नहीं निकाली जाती। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अप्रैल से नए ठेके भाुरू हो जाते हैं पंचायत से रेजोल्यू ान आने के बाद, डिस्ट्रिकट आफिसर से

रिपोर्ट मंगवाने के लिए हमें थोड़ा सा पीरियड मिल जाए तो एक अप्रैल से पहले ठेके बन्द किए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्षः क्या आपका मतलब यह है कि नई औक ान होने से पहले रेजाल्यू ान आ जाना चाहिए ?

चौधरी भोर सिंहः रेजोल्यू ान आने और एक अप्रैल के बीच इतना समय जरूर मिलना चाहिए जिससे हम डिस्ट्रिकट आफिसर से वैरिफिके ान करवा लें।

श्री भाम ोर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस होने की वजह से सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

चौधरी भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस पालिसी से कितना घाटाा हुआ है, यह सवाल नहीं है। हम पिछले साल की फिगर से कम्पेरिजन कर सकते है। पिछले साल 1977–78 में 58 लाख प्रूफ लिटर भाराब उठनी थी लेकिन प्रोहिबि ान की पालिसी के तहत 20 परसैंट कट लग गई जिसके कारण 4640000 प्रूफ लिटर भाराब बिकी। इस साल 13–1–1979 तक 3866660 प्रूफ लिटर भाराब बिकनी चाहिए थी लेकिन बिकी है 3279026 प्रूफ लिटर। यानी 137500830 रूपये का रैवेन्यू आना चाहिए था लेकिन आया 109168680 रूपये और इस तरह से 28332150 रूपये का घाटा हुआ है।

श्री भाम ेर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल को समझा नहीं है। मेरा सवाल यह था कि लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने से सरकार को कितना लौस हुआ है, पहले औक ान हुआ करती थी और बाद में लाटरी सिस्टम लागू कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिस्टम को चेंज करने से सरकार को कितना नुक्सान हुआ है ?

Mr. Speaker: I think he has tried to answer it to the best of his capability. ये मानते हैं कि लौस है, लेकिन यह लौस लाटरी सिस्टम के कारण है या प्रेहिबि ान के ग्रेजुअली इन्ट्रोडक ान के कारण है, इन दोनों के बीच का हिसाब लगाना मु कल है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, राजस्थान के साथ जो हरियाणा का एरिया लगता है, जैसे महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव का एरिया है, यहां पर राजस्थान से हरियाणा में बहुत भाराब आती है। क्या सरकार इस स्मगलिंग को रोकने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भाम ेर सिंहः छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है और हम उनको रोकने की पूरी कोि ा ा करते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने चौधरी भाम ेर सिंह के प्र न के उत्तर में बताया कि इतने प्रूफ लिटर भाराब उठी। अगर उनके आंकड़ों के अनुसार 20 परसैंट प्रोहिसबी ान की वजह से लौंस निकाल दे तो काफी लौस बनता

है ? क्या यह लौस लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस होने की वजह से हुआ हैं या इल्लिसिट डिस्टिले ान की वजह से हुआ है।

श्री भाम ोर सिंहः पिछले साल भी सै ान में यह सवाल आया था और मैंने इसका जवाब भली प्रकार दिया था। टोटल 518 दुकानों में से 123 दुकानों को बन्द करने के लिए रेजालयू ान मन्जरू किए गए। बाकी जितीन दुकानें बची है उनमें से 73 दुकानों के लिए किसी आदमी ने लाटरी नहीं डाली, 5 दुकाने इन्टर स्टेट बार्डर पर होने की वजह से बन्द कर दी आ।र 26 दुकानों की फीस जमा नहीं हुई। घाटा होने का कारण यह है कि जितनी दुकानें पहले थीं उतनी अब नहीं है। जब दुकानें ज्यादा थीं तो 38 लाख प्रूफ लिटर भाराब उठी और बन्द होने से 32 लाख प्रूफ लिटर बिकी।

Ch. Birinder Singh: This is not the answer to my question.

श्री अध्यक्षः मेरे ख्याल में मंत्री जी ने जवाब देने की पूरी कोि ा ा की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल दो करोड़ का घाटा हुआ। औरवह दो करोड़ का घाटाा न ाबन्दी लागू होने की वजह से हुआ है या लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस होने से हुआ हैं, it can not be distinguished. I think, he has given a very good answer.

Ch. Birinder Singh: There is a drop of 40% in revenue. If it is due to prohibition policy then it should have been only 20% and not forty percent.

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि लाटरी सिस्टम के इन्ट्रोड्यूस होने से कोई नुक्सान नहीं हुआ, मैंने कहा है 'हुआ है'। घाटा होने का कारण यह भी है कि 123 दुकानें कम कर दी गई, 73 दुकानें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी ने लाटरी नहीं डाली और 6 दुकानें वार्डर पर होने की वजह से बन्द कर दी गई। इसके इलावा 26 दुकानों की फीस जमा नहीं हुई। हमे 31—1—1979 तक 38 लाख प्रूफ लिटर भाराब उठान चाहिए थी लेकिन दुकानें कम होने की वजह से भाराब कम बिकी और यह घाटा हुआ है।

श्री रण सिंह मानः लाटरी प्रणाली लागू होने से जो हानि हुई है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब पालिसी बनाई गई उस वक्त सरकार के विचाराधीन यह प्र न था कि भाराब के ठेके कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में रह गए हैं। इस प्रणाली को खत्म करने के लिए सरकार ने एक्सपैरिमैंटल बेसिज पर यह लाटर सिस्टम लागू किया ताकि मनोपली न हो और दूसरे लोगों के पास ठेके चले जाएं। इस साल हर एक ठेके को अलग अलग नीलाम किया जाएगा।

श्री जय नारायण वर्मा: क्या कराधान मंत्री कृपया बताएंगे कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो ब्यक्ति हैं, चाहे वे पब्लिक सर्वैंट हैं, चाहे लीडर हैं, वे पब्लिक प्लेस पर भाराब पीकर न घूमें, इस विशय पर क्या सरकार ध्यान देगी ?

चौधरी भोर सिंह: इस सप्लीमेंटरी का मूल सवाल के साज्ञथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्वै चन आवार है, इसमें स्टेटमेंट देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, भाराब के सवाल तक ही सीमित होना चाहिए। (व्यवधान)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जहां पर इल्लिसिट भाराब निकलती है वहां पर ठेके बन्दर करने की प्रणाली पर विचार नहीं यिका जाएगा लेकिन मु कल से एक या दो आदमी होते हैं जो नाजायज भाराब निकालते हैं। इन दो आदमियों की वजह से सबको नुक्सान नहीं होना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और ठेके बन्द करेगी ?

चौधरी भोर सिंह: चार साल में पूरी न ाबन्दी की जाएगी। फिलहाल जहां पर ऐसी जगह हैं जहां आस पड़ोस में नाजायज भाराब बिकती है, हम ठेका रखते हैं, लेकिन अगर एक

दो आदमियों की वजह से ठेका खुला हुआ है तो अगले साल ऐसे ठेके बन्द कर दिए जाएंगे।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, यहां पर कहा गया है ..... it is not in good taste. इसको एक्सपंज करवा दिया जाए।

डाक्टर मंगल सैनः सभी तो नहीं पीते, सारे क्यों मारे जाएं ?

श्री देवेन्द्र भार्माः मैंने सबका नहीं कहा, कुछ की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप इसको जनरेलाईज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र भार्माः मैं आपके कहे बगैर ही अपने भाब्द वापिस ले लेता हूं।

Mr. Speaker: Those remarks should be expunged.

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, एम.एल.ए. होस्टल में दो तीन दिन से तमा ा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप क्वै चन तक ही सीमित रहें। एम.एल.ए. होस्टल में अगर कोई बात है तो अफसोस की बात है और मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरे चैम्बर में मिल लें या मुझे लिखित रूप में दे दें।

लाला बलवन्त राय तायलः कुछ मैम्बर साहिबान ने भी कहा है और मैं भी आपको कह रहा हूं (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, श्री देवेनद्र भार्मा को यहां हाउस में नाम लेना चाहिए कि .....

श्री अध्यक्षः यह क्वै चन आवर है। इसमें नाम पूछने की आव यकता नहीं है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, पिछले साल सरकार ने पालिसी बनाई थी कि भाराब के ठेकों पर से मनोपली खत्म की जायेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एल–वन और एल–टू भाराब के ठेकों को दुबारा नीलाम करने के बारे में विचार कर रहे है ताकि उनकी मनोपली खत्म हो सकें ?

चौधरी भोर सिंहः सभी ठेकों की औक ान करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहब ने सवाल यह किया है कि क्या मनोपली तोड़ने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है ?

चौधरी भोर सिंहः मनोपली तोड़ के लिए पूरे प्रयत्न किये जा रहे है।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): पिछली दफा जो घाटा पड़ा है उसको देखते हुए हमने बोली कराने का फैसला यिका है। हम मनोजली सिस्टम को खत्म करने जा रहे है। जैसा कि पहले

भी बयान किया जा चुका है कि तजुर्बे के तौर पर सिस्टम को चेंज किया था लेकिन उस सिस्टम से घाटाा पड़ा है। उस घाटे को देखते हुए पासिी चेंज कर दी गई है। इस बार एक–एक ठेका नीलाम होगा ताकि मनोपलिस्ट बोली दे कर ज्यादा दुकानों पर कब्जा न कर जायें।

इसके साथ साथ में यह भी हाउस को बताना चाहता हूं कि जो एल–वन और एल–टू की दुकानें अलाट होती थी वे चाहे भाहरों में है या दूसरी जगहो पर हैं उनके बारे में पहले ही फैसला ले लिया है कि सारी नीलाम होंगी।

श्री फतेह चन्द विजः मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हं कि जब भाराबबन्दी को लागू करने के लिए पिछले साल नीलामी सिस्टम को खत्म किया गया था तो फिर से यह सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का पहले ही जवाब आ चुका है।

चौधरी रिजक रामः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ..... भी कोई दुकान का प्रबन्ध किया जाएगा ? (हंसी)

चौधरी पीर चन्दः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गांवों से रेज्योल्यू ान पास कर देने के बाद ठेका बन्दर कर दिया जाता हैं। तो क्या इसी प्रकार से भाहर वाले

भी अगर रेज्योल्यू ान पास करके दे दें तो क्या वहां भी ठेका बन्द कर दिया जायेगा ?

चौधरी भोर सिंहः इस बार हम 40 परसैंट इंडियन मेड फारन लीकर के ठेके घटा रहे हैं और वे भाहरों में ही होंगे।

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नीलामी के दिनों में ठेके वाले प्रचार करते हैं कि 'पीओ और जीओ' क्या इस एडवरटाइजमैंट को बन्द करने का विचार किया जा रहा है ?

चौधरी देवी लालः यह सुझाव पहले ही मंजूर कर चुके हैं।

Resources of Irrigation

***1044. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the steps which are being taken by the Government for increasing the resources of Irrigation in the State;

(b) the arrangements made by the Government for providing more water for Irrigation purposes in the canal outlets working at present; and

(c) whether there is any proposal to widen the outlets; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialised?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) सरकार राजय में निम्नलिखित सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए पग उठा रही है:–

1. अवर्धन तथा सीधे सिंचाई नलकूपों का लगाना।

2. नहरों को पक्का करके पानी का संरक्षण।

3. खालों को पक्का करके पानी का संरक्षण।

4. सप्रिंकलर सिंचाई द्वारा पानी का संरक्षण।

5. यमुना नदी, ड्रैनों तथा उप नदियों के बाढ़ के पानी का प्रयोग।

6. हरियाणा के भाग के रावी ब्यास के फालतू पानी के लाने के लिए सतलुज–यमुना लिंक का निर्माण और

7. भूमि के ऊपर तथा नीचे नये जल भंडारों का बनाना तथा वर्तमान जल भंडारों की क्षमता को बढ़ाना।

(बी) जो अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा उसे वर्तमान सिंचाई प्रणाली में वर्तमान कैपेसिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग मे ंलाया जायेगा जैसे कि सिंचाई नहरों को अधिक दिनों

के लिए चलाने और कोई खास प्रबन्ध करने की आव यकता नहीं होगी। फिर भी कुछ स्थानों पर नहरों तथा मोघों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

(सी) नहीं।

चौधरी हरस्वरूप बूराः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसी आउटलैट को एक एस.डी.ओ. और ओवर सीयर के बदल जाने पर डिसट्रब क्यों कर दिया जाता है और अगर वह भी बदल जाता है तो फिर अगले वाला डिस्ट्रब कर देता है। क्या कोई ऐसी पालिसी बनायी जायेगी कि ओवरसीयर और एस.डी.ओ. के बदलने पर उस मोघे को डिस्ट्रब न किया जाये और उसके लिए टाईम मुकर्रर कर दिया जाये कि इतने दिन बाद डिस्ट्रब किया जायेगा क्योंकि मोघे पर रकबा बढ़ता घटता नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह तय ुदा पालिसी है कि जिस कैपसिटी का आउटलैट हो, उसी कैपेसिटी के हिसाब से उसका साइज होता है। मेरे माननीय सदस्य कोइ ऐसी बात मेरे नोटिस में नहीं लाये कि एस.डी.ओ. और ओवरसीयर के बदल जाने पर उसाक साइज या डिजाइन तबदील कर दिया गया हो यानी घटा दिया गया हो या बढ़ा दिया गया हो। अगर मेरे नोटिस में लायेंगे तो एक ान लिया जायेगा।

श्री भले रामः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रोहतक और सोनीपत के इलाके मे ंबसी लाल की सरकार के टाईम पर पानी पर चालीस परसैंट कट लगा दी गई थी, क्या उस कट को बहाल करने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उस कटौती को एग्जामिन किया जा रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि पिछले राज में करनाल जिले मे ंजिन मोघों को ऊंचा और छोटा कर दिया गया था, क्या उनको फिर से पूरा पानी देने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः हरियाणा के सभी मोघों को दुबारा चैक करवाया गया है लेकिन फिर भी किसी इलाके में ि ाकायत है तो दुबारा चैक करवायेंगे।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो टैम्परेरी राइस सूट्स दिय जाते हैं वे 20 एकड़ के लिए दिये जायें तो भी दस एकड़ को भी पानी नहीं देते हैं, यह हर इंजीनियर और एस.डी.ओ. को पता है, क्या उनके साइज को बड़ा करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस बात को एग्जामिन करवा लेंगे कि जितने रकबे के लिए राइस सूट्स दिया जाता है उतने को पानी

लगता है या नही। एग्जामिन करने के बाद उसी साइज का मोघा लगाया जायेगा।

चौधरी भाग मलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि अम्बाला जिले में ि ावालिक पहाड़ियों के फुट स्टैप्स पर जो स्केटर्ड गांव है वहां पर न तो डीप ट्यूबवैल्ज लग सकते हैं और न ही नहर का पानी लग सकता है, क्या वहां पर डैम बना कर पानी देने पर विचार किया जायेगा ?

श्री अध्यक्षः यह बिल्कुल अलग सवाल है।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, पानी बढ़ाने का जो तरीक मंत्री महोदय ने फरमाया है इससे जो लोग टेल पर हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। क्या मंत्री जी बताएंग कि टेल पर लगने वाले इलाकों के लिए पानी में बढ़ावा देने का भी वे कोई तरीका सोच रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सब माईनर्ज की, सब कैनाल्ज की और सारे वाटर कोर्सिज की लाइनिंग की जा रही है। यह काम पूरा हो जाने के बाद टेल पर पानी न पहुंचने की समस्या खत्म हो जाएगी।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, पंजाब से जो रजबाहे और मोघे हरियाणा की तरफ आते हैं उनका पानी हरियाणा में पहुंचते–पहुंचते काफी कम हो जाता है और टेल पर

पहुंचते पहुंचते तो उनमें कुछ नहीं रहता। क्या मंत्री जी बातएंगे कि उनका भी कुछ प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः माननीय सदस्य यदि कोई खास बात नोटिस में लाएं तो उसका अव य प्रबन्ध करेंगे।

चौधरी ई वर सिंहः मैंने तो लिख कर भी दिया थां

श्री वीरेन्द्र सिंहः मुझे तो नहीं दिया।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं एक बात मंत्री जी के नोटिस में लाया था कि रिवाड़ी खेडा और डेसलपुर में नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगा बल्कि फ्लड का पानी आने के बाद वहां धान की भाक्ल का पटेरा अपने आप ही उग गया लेकिन इनके महकमें वालों ने उसे धान समझ कर लोगों के जिम्मे उगाही लिख दी। क्या मंत्री जी उसकी इंक्वायरी कराएंगे ?

श्री अध्यक्षः अलग मिलकर आप उनसे बात कर लें।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैंने इन्हें यह बात बताई थी लेकिन अलग मिलकर बात नहीं बनी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह मेरे से नहीं मिले, भाायद प्रीत सिंह जी से मिले होंगे। ..... (ाोर) .....

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं बीरेन्द्र सिंह जी से ही मिला था और इन्हें बताया था कि रिवाड़ी खेड़ा और डेसलपुर में नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगा।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, जहां लिफ्ट स्कीम्ज हैं, वहां पर जब नहर का पानी आता है तो बिजली बन्द हो जाती है और परिणामस्वरूप पानी इकट्ठा होकर के नहर से ओवरफलों हो जाता है तथा चारों तरफ सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी भर जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और फसल नश्ट हो जाती है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जुई के पास लोहानी, साहड़वा और रिवासा कई जगह ऐसी है, जहां ओवर फलो हो जाता है, क्या इस ओवरफलो को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ? अगर नहीं तो इस को यूटिलाइज करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सवाल बहुत अच्छा हैं। यह प्रोब्लम भिवानी में बहुत है। (विघ्न) महेन्द्रगढ़ में, जोकि भिवानी के साथ लगता हुआ ही है वहां भी यह प्रौब्लम खास तौर पर है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अफसरान को यह हिदायत दी है कि बिजली की कमी के कारण जो ओवरफलो हो जाता है उसका कोई न कोई प्रबन्ध करो और हम बहुत जल्दी ही यह प्रबन्ध करने जा रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी राजेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उजीना डाइव र्न ड्रेन का भारी मात्रा में जो पानी जमुना मे ंगिरता है, क्या उसे सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने की कोई योजना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उजीना डाइव र्न ड्रेन के बारे में माननयी सदस्य ने जो सवाल पूछा, इसके बारे मे मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम एक नई बात चालू करने जा रहे हैं। हरियाणा मे ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में पहली बार जमीन दोज रिजर्वायर्ज बनेंगे। इस स्कीम के तहत जितनी भी ड्रेन्ज हैं, उनका जितना पानी हम कंजर्व कर सकेंगे, किया जाएगा और उसे आबपा ाी के काम में लाया जाएगा।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, आपको मारफत मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि ये एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज हैं और जिनकी बाबत पिछली सरकार ने यह फैसला किया हुआ है कि सरकार हर ट्यूबवैल के लिए चार हजार फुट नाली देगी और जमींदार अपनी नाली नहीं लगा सकते, क्या इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मूल प्र न से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन चार हजार फुट से आगे नाली यदि जमींदार बढ़वाना चाहते हों तो उनको खुली छूट है कि वे अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं।

चौधरी लाल सिंहः पैसे कौन देगा ? (विघ्न)

Roads taken up for construction

***1027. Roa Ram Narain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) the total number of roads taken up for construction by the Government after the formation of Janata Government in the State;

(b) the district-wise and constituency-wise kilometres of roads constructed so far;

(c) the district wise and constituency-wise total expenditure incurred on the roads as referred to in part(b) above; and

(d) whether it is a fact that the construction of Gurgaon-Bahadurgarh road via Chandu-Badli has not been completed so far; if so, the reasons thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) 31—1—79 तक 1021 सड़कें ।

(ख) एंड (सी) वांछित सूचना का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(डी) हां, जी। सड़क भूमि न अभिग्रहण करने तथा ड्रेन नम्बर 8 पर पुल बनाने के कारण पूरी नहीं हो सकी।

Statement

Statement showing District-wise and Constituency-wise Kilometres of roads constructed and the expenditure incurred during the Janata Government period i.e. from June 1977 to January, 1979.

Sr. No.	Name of District/ Constituency	Length of Road constructed in K.M.s.	Expenditure incurred (Rs. in Lacs)
1	2	3	4
Ambala District			
1	Kalka	15.50	32.26
2	Naraingarh	4.15	8.50
3	Sadhaura	16.52	12.76
4	Chhachhrauli	20.75	13.70
5	Jagadhri	2.28	7.82
6	Yamuna Nagar	6.87	4.63
7	Mullana	6.95	4.75

8	Ambala Cantt.		
9	Ambala City		0.32
10	Nagal	3.55	8.59
	Total	**76.57**	**93.33**
Karnal District			
11	Indri	18.28	17.38
12	Nilokehri	5.27	7.89
13	Karnal	5.10	0.83
14	Jundla	5.07	3.57
15	Gharounda	9.39	5.69
16	Assandh	1.10	5.86
17	Panipat	0.40	0.32
18	Samalkha	1.67	0.43
19	Naultha	2.67	10.03
	Total	**48.95**	**51.80**
Kurukshetra District			
20	Shahbad	7.96	12.53
21	Radaur	22.78 +3.40	18.26 +2.69

22	Thanesar	16.45	14.15
23	Pehwa	9.61	18.75
24	Gulha	29.90	48.42
25	Kaithal	1.90	4.56
26	Pundri	6.77	4.67
27	Pai	1.70	3.93
	Total	**100.47**	**128.56**
Rohtak District			
28	Hassangarh		0.50
29	Kiloi		1.04
30	Rohtak		
31	Meham	0.40	0.77
32	Kalanaur	4.50	5.19
33	Beri		2.50
34	Sahlawas	6.30	9.21
35	Jhajjar		12.22
36	Badli	3.00	5.60
37	Bahadurgarh	0.70	0.67
	Total	**16.75**	**37.66**

Sonepat District			
38	Baroda	16.57	12.99
39	Gohana	5.00	4.77
40	Kailana	9.02	5.92
41	Sonepat		
42	Rai	6.75	3.65
43	Rohat	0.31	1.28
	Total	**37.65**	**28.61**
Jind District			
44	Kalayat	6.17	6.84
45	Narwana	2.90	7.68
46	Uchana	3.60	2.47
47	Rajaund	0.50	0.29
48	Jind	0.90	0.60
49	Jullana	7.84	6.15
50	Safidon	7.80	9.13
	Total	**29.71**	**33.16**
Gurgaon District			
51	Faridabad	0.70	0.96

52	Moola Maharajpur	7.12	3.93
53	Ballabgarh	9.97	6.70
54	Palwal	5.93	7.23
55	Hassanpur	22.78	21.04
56	Hathin	0.63	0.43
57	Ferozpur Jhirka		
58	Nuh	5.41	3.09
59	Taoru	7.79	8.97
60	Sohna	7.27	6.36
61	Gurgaon	0.40	0.43
62	Pataudi	4.14	3.45
	Total	**72.14**	**62.60**
Bhiwani District			
63	Badhra	11.08	6.33
64	Dadri	0.85	3.42
65	Mundhal	9.26	9.65
66	Bhiwani	4.88	8.76
67	Tosham	12.34	8.68
68	Loharu	9.98	4.13

69	Bawani Khera	11.05	11.15
	Total	**59.44**	**52.12**
Hissar District			
70	Barwala	4.75	4.49
71	Narnaund	24.44	36.86
72	Hansi	2.08	0.43
73	Bhattu Kalan	18.27	25.57
74	Hissar		
75	Ghirai		2.20
76	Tohana	14.01	11.23
77	Ratia	23.05	25.61
78	Fatehabad	3.60	3.74
79	Adampur	6.67	6.75
	Total	**96.87**	**156.88**
Sirsa District			
80	Darba Kalan	24.70	50.17
81	Ellanabad	35.97	31.44
82	Sirsa	7.20	6.31
83	Rori	49.38	48.39

84	Dabwali	33.36	33.62
	Total	**150.61**	**169.93**
Mohindergarh District			
85	Bawal	5.30	8.28
86	Rewari	13.70	11.67
87	Jatusana	14.40	8.09
88	Mohindergarh	11.66	7.96
89	Ateli	4.94	2.74
90	Narnaul	1.70	1.54
	Total	**51.70**	**40.28**
	Grand Total	**744.45**	**854.93**

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, मेरा हल्का पलवल में केवल 5 किलोमीटर सड़क बनी है जबकि और जगह 40 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब पिछली दफा यह तय हुआ था कि सब जगह बराबर सड़कें बनेंगी तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अभी कल ही आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के अन्दर अनाउंसमैंट की है कि अगल इलैक ान से पहले हरियाणा के तमाम गांव को पक्की सड़कों से

जोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसी मैम्बर साहब को यह फिक्र नहीं होना चाहिए कि कौन सी जगह सड़कें पहले बन रही हैं। 1982 से 6 महीने हर गांव को सिंगल लिंक से जोड़ दिया जाएगा। इसमें चिन्ता की कोइ बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः मेरे ख्याल में मुख्य मंत्री जी की अ योरैंस के बाद इस सवाल के बारे में ज्यादा सप्लीमैंटरीज करने की गुंजाय ा नहीं रह जाती।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, जो गांव सरकार की डारैक्टरी में नहीं हैं क्या उनमें सड़क नहीं बनेगी ?

श्री लछमन सिंहः ये बता दें, उनमें बना देंगे।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, साल्हावास हल्के की 6.30 किलोमीटर सड़कों की जो फिग्गर दी गई है यह बिल्कुल गलत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस साल मेरे हल्के में ये कौन सी सड़कें टेक अप कर रहे हैं ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, यह फिगर अगर गलत है तो इसके बारे में ये मुझे अलग से मिल लें, दफतर वालों से पूछ कर इनकी तसल्ली करवा देंगे। अगर गलती होगी तो ठीक करवा दी जाएगी।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से एक बात दरयाफत करना चाहूंगा।

गुड़गांव जिले की पांच कांस्टिचुऐंसीज की स्टेटमेंट हाउस की टेबल पर रखी गई है। स्टेटमेंट के सीरियल नं. 56 से 60 के अनुसार आपने केवल 15.1 किलोमीटर सड़कें बनाई है जबकि सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पांच कांस्टिचुएंसीज में 150.61 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि तवाडू कांस्टिचुऐसी के 56 विलेजिज सड़कों के साथ अनकुनैक्टिड हैं। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन कांस्टिचुऐंसीज में ज्यादा गांव बाकी है उनको प्रैफरैन्स दी जाएगी ?

10.00 बजे

श्री लछमन सिंहः मैं नहीं समझता स्पीकर साहब कि खुर ाीद भाई, जो एक पुराने पार्लियामैटेरियन हैं और जो सीधी जुबान में सवाल पूछते हैं, सी.एम. साहब ने जब यह कह दिया है कि 1982 तक सारे गांवों को पक्की सड़कों से सिंगल लिंक से जोड़ दिया जायेगा फिर भी इनको इतनी चिन्ता क्यों हैं ? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस बारे में उन्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। डेट फिक्सड है। कोई गांव आज जुड़ जायेगा तो कोइ कल जुड़ जायेगा। ..... (ाोर व व्यवधान) .....

(इस समय बहुत से सदस्य खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्षः मेरा ख्याल यह है कि मंत्री जी ने अ योरैन्स दी है और मुख्य मंत्री जी नेभी अ योरैन्स दी हुई ळै,

इसलिये इसमें ज्यादा सप्लीमैंट्रीज पूछने की गुजांई ा नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर) आर्डर प्लीज। देखिये अगर कवै चन आवर में ऐसे होगा तो बहुत सा वक्त तो जाया होगा ही और जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आगे आ रहे हैं वह रह जायेंगे इसलिए थोड़ा सा भाांति से काम लें।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार यह है कि आप इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्क ान अलाऊ कर दीजिये। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः देखिये अगर सारे मैम्बर साहेबान चाहते हैं कि इस पर हाफ एन आवर डिस्क ान हो, तो मेरे को इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन .....

आवाजेंः जब सी.एम. साहब ने कह दिया है कि 1982 तक सारे गांवों को जोड़ दिया जायेगा, तो कोई जरूरत नहीं है।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मुझे बोलना पड़ेगा। जो साहेबान अपने अपने हल्के की बाबत सड़कों का सवाल उठा रहे हैं, आमतौर पर उनका उन हल्कों से कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए इस बारे में पहले भी डिस्क ान हो चुकी थी और कल आपके सामने आया है कि एजुके ान के मामले में सिरसा जिला का क्या हाल है ? वह सबसे पिछड़ा हुआ रहा है। इसी तरह से सड़कों के मामले में भी हमें बहुत पिछड़ा हुआ रखा गया और ऐसा मजाक बनाया था जैसा कि मैंने पिछली दफा

भी जवाब दिया था कि कई जगह पर जाने के लिए अगर 3–3, 4–4 मील का फासला पूरा कर दिया जाता तो 30–30 मील की बचत हो जाती। तो चौधरी भजन लाल जी की मेहरबानी से मुझे वह दुक्ष उठाना पड़ा था। इस तरह से मेरे हल्के में एक अढ़ाई मील का एक टुकड़ा बनाने से जो भट्टू से फतेहाबाद होकर हिसार सडत्रक जाती थी, 30 मील का फासला कम हो गया है। उससे 30 मील का सफर जो पहले करना पड़ता था, वह अब बच गया है। वह एक मिसिंग लिंक था। इसी तरह से जंगवाड़ा से गंगा सागर साढ़े तीन मील का टुकड़ा था। मैंने सभी चीफ इंजीनियर्ज से कोि ा ा करके देख ली थी। लगातार 15 साल मेरी कोि ा ा होती रही लेकिन वह पूरा नहीं हो सका था। अब वह अढ़ाई साढ़े तीन मील का टुकड़ा बन जाने से 25 मील का फासला कम हो गया है। अब डबवाली से होकर सिरसा जाने की बजाये आप सीधा सिरसा जा सकते हैं। इसी वास्ते मैंने अब यह एलान कर रखा है कि सड़कों की बाबत मेरा यह फैसला है कि किसी हमारे आदमी को आप वोट न दें, अगर वह कार में न आये। इसलिये सिवाये इसके कि हाउस का टाईम वेस्ट हो, मेरा ख्याल है इसमें कोई सैन्स नहीं है।

Construction of link roads in Jhajjar Constituency

***1058. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Public Work be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to construct link roads in Jhajjar Assembly Constituency; if so, the details thereof together with time by which these are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): हां जी, सड़कों का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इनके निर्माण के लिए समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Statement

Detail of roads proposed to be constructed in Jhajjar Constituency

Sr. No.	Name of Road	Total Length	Balance Length in Kms. on 31-1-79
1	2	3	4
1	Gudiyani to Ahmadpur Partal	2.70	1.70
2	Newla to Usmanpur	1.50	1.00
3	Chhuchakwas to Koyalpuri	8.00	
4	Ahir to Chhapr	6.15	3.95
5	Jhajjar Chhuchakwas	2.00	2.00

	road to Kheri Hoshiarpur		
6	Dawala Karodha to Rankhanda	1.50	1.50
7	Subana to Sarola	2.50	2.50
8	Koyalpuri to Chandwana	2.50	2.50
9	Shahjannpur approach road	0.31	0.31
10	Fatehpuri to Kanwa	0.50	0.50
11	Hassanpur to Kunjia	2.70	2.70
12	Diwala to Karoda	5.10	5.10
13	Bindawas drain to Fatehpuri Bridge	5.50	5.50
14	Bindawas drain to Bilochpura	2.80	2.80
15	Usmanpur to Kahnanri	1.25	1.25
16	Gawalson to Taloo	3.90	3.90
	Total	**48.91**	**37.21**

कैप्टन मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो लिस्ट इन्होंने दी हैं, उसके अलावा भी मंत्री महोदय जो मेरी कांस्टीच्यूएंसी में वायदा करके आये हैं कि छूछकवास से भिडंरवास तक, कहौरी से छपार व तालाब से गवाली तक, सड़कें जल्दी बनायेंगे, तो क्या उन सड़कों को बनाने के लिए कार्यवाही करेंगे या कर रहे हैं ?

श्री लछमन सिंहः जी हां, जहां–जहां वायदा करके आये हैं, वहां पर जरूर बनायेंगे।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य सवाल पूछने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः देखिये, इस विशय में हम काफी से ज्यादा टाईम लगा चुके हैं और जब तमाम मैम्बर साहेबान को चीफ मिनिस्टर साहब ने यह आ वासन दिलाया है कि वहां पर सड़कें अव य ही 1982 तक बना दी जायेंगी, तो इस पर बहुत ज्यादा टाईम जाया नहीं करना चाहिए।

Construction of Roads

***1048. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government intends to construct roads from Ellenabad to village Thobria, Rania to village Jhovar via village Sultanpuria and from Rania to Tharji

Satnam Singh on which the earth work has been done by the people themselves together with the time by which these are likely to be consructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): इन सड़कों को बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, एक सप्लीमैंट्ररी मुझे पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल के ऊपर तो बहुत से सप्लीमैंट्ररी मुझे पूछ जा चुके है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल रैलेवैन्ट सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी, यह सवाल चौधरी भागी राम का है और उनकी कांस्टीच्यूऐंसी से ताल्लुक रखता है। इसमें कोई सप्लीमैंट्री पूछने की गुजांई ा नहीं है।

चौधरी गंगा राम: मैं तो इससे अलग सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि गोहाना .....
..

श्री अध्यक्ष: इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

Evacuee Property

***1041. Sh. Jai Narain:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total property of evacuees, who migrated to Pakistan and which now vests in the Custodian, available in the State,

(b) the number of persons to whom the said proerty has been given in the State, district-wise during the current financial year 1978-79 upto 28th February, 1979; and

(c) the detail of the property which is still left for distribution amoungst the Harijans and the ex-servicemen?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) राज्य में भिन्न–भिन्न प्रकार की 1–2–79 की कुल उपलब्ध मतरूका भूमि सम्पतियां निम्नलिखित अनुसार है:–

भाहरी					**ग्रामीण**			
पूर्णरूपेण मतरूका साधारण एकड़ में	मौरूसी हकूक के तहत साधारण एकड़ मे	संयुक्त का ात साधारण एकड़ मे	गैरमुमकिन साधारण एकड़ मे	मकान/ प्लाट	का ाता भूमि स्टैण्डर्ड एकड़ में	बंजर साधारण एकड़ में	गैरमुमकिन साधारण एकड़ मे	मकान/ प्लाट

375		8	48	1048	4323	1572	4676	11098

(बी) व्यक्ति जिनको भूमि/सम्पतियां वर्श 1978–79 में जैसा कि 31–1–79 तक बेची/अन्तरण की गई हैं, 1722 हैं। जिनका जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दियसा गया है।

(सी) मतरूका भूमि/सम्पतियां जो अभी हरिजनों को बेचने के लिए उपलब्ध हैं (भूतपूर्व सैनिकों को कोई छुट नहीं है) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

ग्रामीण भूमि		**ग्रामीण प्रापर्टीज**	
का ाता भूमि स्टैण्डर्ड एकड़ में	बंजर साधारण एकड़ में	गैरमुमकिन साधारण एकड़ मे	मकान/ प्लाट
3314	1255	3440	5084

अनुबन्ध – 1

क्रमांक	जिला का नाम	व्यक्तियों की संख्या जिनको मतरूका भूमि/प्रापर्टीज वर्श 1978–79 में 31–1–79

		तक बेची गई
1	2	3
1	हिसार	48
2	भिवानी	252
3	गुड़गांव	413
4	अम्बाला	181
5	करनाल	274
6	रोहतक	54
7	कुरूक्षेत्र	54
8	सोनीपत	88
9	महेन्द्रगढ़	24
10	सिरसा	240
11	जीन्द	94
	कुल जोड़	**1722**

श्री जय नारायणः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कितनी जमीन ऐसी है जोकि अभी कस्टोडियन के पास है, औश्र अलाट होनी बकाया है ? क्या यह इन्फर्मे ान डिस्ट्रिक्ट वाईज देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः इसका तो जवाब आ लिया। जवाब में यह बताया गया है कि इतनी जमीन अलाट कर चुके हैं।

श्री भाम ोर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जैसे कि उन्होंने जवाब में बताया है कि 3314 एकड़ भूमि ऐसी है जो अभी हरिजनों में अलाट की जानी है, यह कब तक अलाट कर देंगे ?

श्री प्रीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके बारे में चीफ सैटलमैंट आफिसर के पास केस चल रहे हैं। जमीनों के ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको खाली यकरवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जब यह खाली हो जायेगी तो भीघ्र ही उनकी नीलामी कर दी जायेगी।

कंवर राम पाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐवेकु प्रोपर्टी है वह सिर्फ हरिजनों को ही दी जाती है या जो लैंडलैस एक्स सर्विसमैंन हैं उनको भी अलाट की जाती है ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब दिया जा चुका है कि यह जमीन एक्स सर्विसमैंन के लिए नहीं है सिर्फ हरिजनों के लिए है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो कस्टोडियन की जमीन है या ऐवेकु लैंड है और लोगों के कब्जे में हैं उसको कब तक खाली करा कर हरिजनों में बांट देंगे ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब दिया जा चुका है।

चौधरी गया लालः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कस्टोडियन की जमीन या सरप्लस जमीन जो काफी अर्से से लोग दबाये बैठे हैं उनसे वह जमीन कब तक खाली करीा कर हरिजनों में बांट दी जाएगी ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, कस्टोडियन की जो जमीन रिफूजियों को दी गई थी उसके बाद वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि यह जमीन हमारी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी तजवीज है कि वक्फ बोर्ड और कस्टोडियन डिपार्टमैंट वाले आपस में फैसला कर लें कि जिनको वह जमीन मिली थी उन पर दावा न किया जाए ?

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है और जो झगड़े होते हैं एक्ट के तहत अदालतों मे वे निपटाए जाते हैं।

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब, भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पर अमल करने में काफी अड़चन आ रही है और जो लोग जमीन दबाए बैठे हैं, वे खाली नहीं करते। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार सैन्ट्रल गवर्नमैंट को रिकमेन्ड करेगी कि जमीन के बारे में जितने कानून हैं उनको नाइन्थ ि ाड्यूल में डाल दें ताकि कोई अदालत में न जा सके ?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल ऐवेकु प्रापर्टी के बारे में है सरप्लस जमीन के बारे में नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन खाली करवाई है और अभी कितनी जमीन बाकी रहती है ?

श्री प्रीत सिंह: इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्युऐसी कैथल में एक धर्मपुरा अटेला गांव है, वहां एक जंगल बीस साल के लिए लिया था और उन लोगों ने उस जंगल को तोड़ा और तोड़ने के बाद आज वह जमीन सरप्लस में आ गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह जमीन उन लोगों को ही दी जाएगी जिन्होंने वह जंगल लिया था या दूसरे लोगों को दी जाएगी ?

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, मुझे पता नहीं, मेरे लायक दोस्त किस जमीन की बात कर रहे हैं। मुझे तो उस जमीन के बारे में पता नहीं है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, जो कस्टोडियन की जमीन है उसकी तीन–तीन दफा नीलामी होती है और हर बार जो नीलामी होती है वह पहली बोली से ज्यादा होती है लेकिन वह बोली कंफर्म नहीं होती है जिससे हरिजन भाइयों को बड़ा नुक्सान होता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह बोली कंफर्म क्यों नहीं होती है ?

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, एक जमीन की नीलामी करने के लिए पहली दफा डेट फिक्स की जाती है और उसकी आक ान होती है। जो बिडर है या परचेजर है वह बिड देता है लेकिन वह परचेजर रेगूलरली इंस्टालमैंट नहीं देता और फिर उस नीलामी को कैन्सिल करके दुबारा डेट फिक्स की जाती है। क्या दुबारा नीलाम करने का यही कारण है ?

श्री अध्यक्षः बिडर से जो पैसा लिया जाता है क्या वह वापिस कर दिया जाता है ?

श्री प्रीत सिंहः नियम ऐसा है कि वह पैसा फोरफीट हो जाता है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, स्वामी जी का सवाल बिल्कुल ठीक है गांव के किसान की जमीन छीनने के

लिए तो जमीन पर सीलिंग लगा दी है क्या मंत्री महोदय भाहर की प्रापर्टी पर पाबन्दी लगाकर इसको भी छीनने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रीत सिंहः यह सवाल कस्टोडियन की जमीन के बारे में है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, हरियाणा में ऐसे देहात है जहां ऐवेकु और नौन ऐवेकु बिसवारदन की जो भाामलात देहभूमि है वह कस्टोडियन के कर्मचारियों ने या तो अलाट कर दी है या नीलाम करना चाहते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिससे कि नान–ऐवेकुज को हिस्सा मिले और उनके राइट्स सुरक्षित रह सके ?

श्री प्रीत सिंह : इसको एग्जामिन करवा लेगे।

चौधरी भाग मल : स्पीकर साहब, हाउस में बताया गया है कि ऐवेकु और कस्टोडियन की जमीन पर दस परसैन्ट ड्यूटी लगी हुई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने अ ाियोरैस दी है कि यह ड्यूटी हटा देंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्यूटी को हटाने के कब तक आर्डर इ ाू हो जाएंगे ?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, यह बात सरकार के विचारधीन है और जल्दी ही आर्डर्ज इ ा हो जाएंगे।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, ऐसा होता है कि हरिजन के नाम से गैर–हरिजन बोली दे देते और कुछ समय के बाद उस हरिजन को कुछ पैसा देकर अपने नाम जमीन को करा लेते है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या सरकार के विचारधीन कोई ऐसी तजबीज है जिससे गैर हरिजन बोली न दे सके ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सब बैनामियां खत्म हो जाएगी अगर सरकार यह कर दे कि हरिजन एक किस्त दे दे तो जमीन का इंतकाल उस हरिजन के नाम कर दिया जाए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि बार–बार नीलामी को रोकने के लिए सरकार के विचारधीन क्यो ऐसी कोई तजबीज है?

श्री अध्यक्ष : अगर वह पैसा न दे तो इन्तकाल उस आदमी कै नाम कैसे हो सकता है।

चौधरी गंगा राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सरकार के विचार– धीन कोई ऐसी बात है कि कस्टोडियन की जमीन हरिजनों को देने के अलावा बैकवर्ड क्लास के व्यक्तियों को भी दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले भी बैकवर्ड क्लास के लोगौं को दी जाती है और ये लोग उनमें इंक्लूड है।

कामरेड भांकर लाल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड लोगों के साथ साथ जो झुग्गी झोपडी वाले लोग तपडीवास है इनको भी इस किस्म की जमीन देने के विचार है?

श्री अध्यक्ष : अभी भी टपरीवास ि ाड्यूल्ड कास्ट्स में इंक्लूडिड है।

Adult education contres for adult Harijans

***1076. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Education be pleasad to State whether there is any propoal under consideration for the Government to open Special Adult Education Centres under the Adult Educdation Schemes for providing education facility to the adult Harijans; if so, the deatiled arrngmeants likely to be made to educate Harijan woman in rural ares of the State?

ि **ाक्षा मंत्री** (श्री हीरा नन्द आर्य) : जी हां राश्ट्रीय प्रौढ ि ाक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सामान्य कैटेगरी के प्रौढो के लिए, जिन में अनुसूचित जाति के प्रौढ भी प्रवे ा पा सकते है, खोले गए प्रौढ ि ाक्षा केंन्द्रो के अतिरिक्त केवल अनुसूचित जाति के प्रौढों के लिए भी प्रौढ ि ाक्षा केद्र खोले गये है। महिलाओं के लिए भी प्थक रूप से बडी संख्या मैं प्रौढ ि ाक्षा खोले गये है तथा कुछ हरिजनों महिलओं के लिए भी खोले गये है। जहां तक

सम्भव हो सका है, इन केन्द्रों में अनुदे ाक तथा पर्यवेक्षक के पदों पर महिलओं की नियुक्तियां की गई है।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, मै ि ाक्षा मंत्री महोदय के पूछने चाहता है कि जिला गुडगांव में कितने प्रौढ ि ाक्षा केद्र खोले गये है और कितने आबादी के लिए प्रौढ ि ाक्षा केंद्र खोलने का काइटेरिया है?

श्री हीरा नन्द आर्य : प्रत्येक जिले में 300 प्रौढ ि ाक्षा केन्द्र खोलने का विचार है गुंडगांव में हरिजनों के लिए 96 केन्द्र खोल दिये गये है जिन में से 62 पुरूशों के लिए और 34 स्त्रियों के लिए खोले गये है?

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतांएगे कि हरियाण में जितने प्रौढ ि ाक्षा केन्द्र खोले गये है, उन में से पलवल में प्रौढ ि ाक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी और हरिजनों के नाम से कितने है?

श्री हीरा चन्द आर्य : स्पीकर साहब, इस सवाल में तो डिस्ट्रिकट– वाईज सूचना भी नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब इन्होने पलवल का भी पूछ लिया, कल को यह घरवाईज पूछना चाहेगे, अतः इसके लिए इनको अलग से नोटिस देना होगा।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब ने प्रत्येक जिले के बारे में बता दिया है। अगर आप कांस्टीचुएन्सी– वाईज पूछना चाहेगें तो इसके लिए आपको अलग से नोटिस देना होगा।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, जो प्रौढ ि ाक्षा केन्द्र सरकार ने खोल रखे है, मैने वहां पर जाकर देखा है कि उन में बूढे और माताएं पढ रही है लेकिन हालत यह है कि जो माताएं है उनकी उंगलियां गोबर पाथ–पाथ कर मोटी हो गई है और जो बूढे है उनकी उंगलियां हल चला–चला कर मोटी हो गई है, जिस की वजह से ये बेचारे एक हरफ भी लिखने में समर्थ नहीं है तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इन्होने कभी इन केन्द्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है कि वहां पर क्या हालत है?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, है जाकर देख कर आया हूं। हमारे केन्द्र अच्छी प्रकार से चल रहे है। वहा पर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि केन्द्रो की हालत खराब हो जाए। अतः सरकार को पूरी आ ाा है कि मे केन्द्र पूरी तरह से पफले रहे है और होंगे।

श्री भाम ोर सिंह : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएगे कि जो एडल्ट एजुके ान की स्कीम के तहत ये केन्द्र खोल रहे है इन पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, यह पैसा इन्ही केन्द्रो पर खर्च हो रहा है या कि आर0एस0एस0 के लोगों पर खर्च किया जा रहा है?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल बधवा) : स्पीकर साहब इनको तो कोई गोलियां देनी चाहिए ताकि इनके

अन्दर जो आर0एस0एस0 बालो का फोबिया हुआ है वह दूर हो जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय आनरेबल मेम्बर साहिब ने जो आर0एस0एस0 वालों की बात कही है, इन केंन्द्रों में ऐसी कोई बात नहीं है हम किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करते है। जो इस कार्यक्रम को मानते हो, उन के लिए सरकार की स्कीम के अनुसार केन्द्र खोले जाते है।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, इन से पूछे कि क्या ये इस काम में मदद देने के लिए तैयार है?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सरकार की और से इन प्रौढ से इन प्रौढ केन्द्रों मे जो टीचर्ज और टीचरैसिज, बूढे और बूढियों को पढने के लिए लगाये गये है, वे लोग भाहरों के रहने वाले है उन्हे उन देहती पढ़ने वालो से बू आती है और वे पाऊडर वगैरह लगा कर जाते है (भाोर) चण्डीगढ़ से लोग जाते है।

श्री अध्यक्ष : लााल सिंह जी आप सलाव पूछिये ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब सवाल ही पूछे रहा हूं क्या उन भाहरी टीचर्ज और टीचरैसिज के स्थान पर गांवो के लोग ही पढ़ाने के लिए लगाये जाएंगे ताकि वे लोग उन गांव वालों को इट्रैस्ट के साथ पढ़ा सकें?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, जो प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्र खोले गये है, उनमें सरकार की पालिसी के अनुसार उसी गांव की महिलाएं और ि ाक्षक ही होंगे मतलब कि पहले उन्हीं गांवों के लोगों को इस के लिए प्रेफरैन्सा दिया जाएगा, उसके बाद हमे अगर वहां लोग अवेलेबल न होंगे तो फिर पड़ोसी गांव का नम्बर होगा। चण्डीगढ़ का नम्बर तो बड़ी देर के बाद आएगा।

श्री अध्यक्ष : यानी आपका मतलब कि वे क्वालीफाईड होने चाहिए, बी0एड0 या जे0 बी0 टी0?

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, इसमें मैट्रिक, बी0ए0, बी0एड0 की कोई कंडी ान नही है। केवल यह देखा जाता है कि जिस को सरकार पढ़ाने के लिए लगा रही है, वह ि ाक्षा भी दे सकता है या नहीं।

श्री मूल चन्द मंगला : अध्यक्ष महोदय, आठ साल पहले के अन्दर एक एडल्ट एजुके ान के लिए सैन्टर खोला गया था, जिस पर सुपरवाईजरी स्टाफ के लिए 500 रूपये के करीब खर्चा आ गया लेकिन वहां से पांच आदमी भी पढ़कर नहीं निकले थे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन सैन्टर्च की भी वैसी दं ाा तो नही है जो कि कांग्रसी राज में थी? क्या यह बात उनके ध्यान में है कि ये सैन्टर कामयाब भी होंगे या नहीं?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसी तो कई बात नहीं है। जितना हमारे साथी सहयोग करेंगे ही हम कामयाब होंगे।

चौधरी संत कंवर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन अडल्ट एजुके ान केन्द्रो के अन्दर जो कैन्डीडेट्स ि ाक्षा ग्रहरण कर रहे है, उनके एग्जमीने ान का क्या काइटेरिया है ? वे लोग किसी बोर्ड के अन्दर होंगे या किसी और के ताकि यह जायजा लिया जा सके कि ये केन्द्र ठीक ढंग से काम कर रहें है कि नहीं।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, इन केन्द्रो का किसी बोर्ड वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक इन केन्द्रो के ठीक चलने का सवाल है, इस बारे में समय समय पर इन्स्पैक ान होती रहती है और पढ़ने के वालों को सटिफिकेट भी दिये जाते है और पूरी तसल्ली करने के बाद दिये जाते है।

श्रीमति भान्ति देवी : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय ये यह पूछना चाहती हूं कि ये एडल्ट एजुके ान के लिए सरकार की तरफ से केन्द्र खौले गये है उन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और सब से अधिक इन केद्र खोले गये है, उन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और सब से अधिक इन केन्द्रों पर लगाये गये सुपरवाइजरी स्टाफ, आफिर्ज वगैरह पर खर्च किया जा रहा है।क्या हरिजनों को भी इन केन्द्रो से कोई लाभ हो रहा है और कितने केन्द्र हरिजनों के लिए खोले गये है?

श्री हीरा चन्द आर्य : अध्यक्ष महोदयसस, मैम्बर साहिब इसके लिए अलग से नोटिस दे दे या मेरे आफिस में आ जाएं, उन्हें पूरी सूचना दे जाएगी।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा : स्पीकर साहब में आपकी मारफल मंत्री महोदय मै यह पूछना हूं कि यह ..... होता रहा है, यह आगे कब तक चलेगा?

आवजे : यह ..... वर्ड अन–पलियामैटरी है। इसको एक्सपन्ज किया जाए। (भाोर)

Mr. Speaker : I will check it up. If it is un – parliamentary, it wills be expunged.

चौधरी देस राजः अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन एडल्ट एजुकें ान सैन्टर्ज के लिए जो टीचर्ज या टीचर्ज रखे जाते है, क्या उस वक्त उनकी उम्र का भी ध्यान रखा जाता है?

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्ज का ताल्लुक है उनकी उम्र कोई लगभग 30 साल की होनी चाहिए और वैसे साधारण तौर पर जो उम्र होती है, उसके हिसाब से टीचर्ज वगैरह रख लिये जाते हैं।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, एडल्ट एजुके ान स्कीम के अन्तर्गत जो दो–तीन नई स्कीमें जैसे फारमल एजुके ान और फंक ानल लिटरेसी। (ाोर)

आवाजें: स्वामी जी, आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, हिन्दी में बोलिये (ाोर)

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ भाब्दों का अनुवाद नहीं हुआ है, इसलिये स्वामी जी को अंग्रेजी बोलने की पूरी आज्ञा है। (ाोर एवं हंसी)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से इन प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्रों के माध्यम से दो तीन प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें लिखाई पढ़ाई का काम होता है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिये मूल ज्ञान की सिखलाई के लिए भी कोई केन्द्र खोले गये हैं ताकि वे गरीब लोग उन केन्द्रों से ि ाक्षा प्राप्त करके अपनी रोटी रोजी कमाने के काबिल हो सकें ?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जो प्रौढ़ ि ाक्षा का कार्यक्रम है उसको राश्ट्र नीति में भाामिल किया गया है और उसके अनुसार लोगों को लिखाई पढ़ाई, एवं सिलाई और कढ़ाई वगैरह सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सकें और इस काम के लिए सरकार की तरफ से साधन भी जुटाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: 'फ्राड' भाब्द अन–पार्लियामेंटरी है। That will be expunged.

आवाजें: स्पीकर साहब हमें एक सप्लीमेंटरी की इजाजत दे दीजिये। (ाोर) बड़ा जरूरी है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Octroi rates in the Municipal Committees

***1096. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether it is a fact that the octroi rates in the Municipal Committees in the State are different from each other; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to bring uniformity in the octroi rates of Municipal Committees throughout the State?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): वर्तमान आकट्राय भौडयूल में चूंगी के दर सभी नगरपालिकाओं में लगभग समान हैं। हाल ही में सरकार ने वर्तमान आक्ट्राय को सं ाोधित करने तथा एकरूपता लाने के लिए स्थानीय भाासन मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।

Digging of drains in District Rohtak

***874. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which the digging work of Pakasma, Gandhra, Simli and Kultana drains in Rohtak is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): पाकस्मा और गांधरा ड्रेनों की खुदाई का बहुत सा कार्य जून, 1979 तक पूर्ण हो जायेगा और भोश जून, 1980 तक।

बूपनिया, छुड़ानी, कुलताना, सिमली ड्रेन पर कार्य छारा और बूपनिया में मध्य जून 1979 तक पूर्ण हो जायेगा और भोश कार्य जून, 1980 तक किया जायेगा।

इन तीनों ड्रेनों को इससे पहले केन्द्रीय सरकार और देहली प्र ाासन पूर्ण करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन ड्रेनों के पानी का निकास मंगेसपूर ड्रेन और नजबगढ़ ड्रेन के माध्यम से होना है जिन्हें इस क्षमता के लिए अभी बनाया जाना है।

Reduction/enhancement in the commission of Arhties

***1092. Sh. Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that commission of the Arhties was reduced from 2% to 1½ % during the last year in the State; if so, the reasons therefor; and

(b) whether the Government has again raised the afore-said commission from 1½ % to 2%, if so, the reasons therefore?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) Yes. The commission of the kacha arhties was reduced from 2% to 1½ % in November, 1977, by Haryana Agricultural Marketing Board, as it was felt that the reduced rate should suffice keeping in view the nature of services rendered by them.

(b) Yes. Subsequently, however, keeping in view the representation from the traders, it was folt that the reduction would adversely affect the quality of services rendered by the kacha arhties and the commission of Rs. 2% was restored in November, 1978, by the Board.

Cost of production of Paddy

***1053. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether the Government has got assessed the cost of production of various varieties of Paddy (Basmati, Jhone and Jaya etc.) in the State during the year 1978; and

(b) if so, the name of institutions from where it has been got assessed and the cost worked out?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) Yes.

(b) The field data for working out cost of production is collected by the Economic and Statistical Organisation of Haryana and on the basis of this data the cost of production is calculated by the Department of Agriculture. The cost of production worked out for the year 1978-79 for various varoieties is as under:-

Sr. No.	Variety of Paddy	Cost of production worked out (Rs. per quintal)
1	Paddy HY/- (I.R.8 & Jaya)	85.00
2	Paddy (Basmati)	110.00
3	Paddy (others Jhona etc.)	95.00

Water Supply Schemes

***1028. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) the district wise and constitutuency wise number of new water supply schemes for the supply of drinking water which have been taken up by teh Janata Party Government since its assumption of office; and

(b) the cost involved in and the expenditure so far incurred on each said scheme separately?

Public Works Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a)&(b) Statements for 'A' & 'B' above are laid on the table of the House.

STATEMENT – A

District and Constituency wise details of new Water Supply Schemes District Wise

Sr.No.	Name of District	No. of new w/s schemes started
1	Ambala	28
2	Bhiwani	21
3	Gurgaon	13
4	Hissar	35
5	Jind	10
6	Karnal	2

7	Kurukshetra	2
8	Mohindergarh	12
9	Rohtak	21
10	Sirsa	25
11	Sonepat	5
	Total	174
Constituency wise		
Sr.No.	Name of Constituency	No. of new w/s schemes started
1	Kalka	21
2	Naraingarh	5
3	Yamuna Nagar	1
4	Chhachrauli	1
5	Bawani Khera	4
6	Mundhal	5
7	Dadri	3
8	Bdhra	4
9	Loharu	5
10	Gurgaon	4

11	Sohna	2
12	Hathin	2
13	Ferozpur Jhirka	1
14	Nuh	2
15	Taoru	2
16	Narnaund	11
17	Barwala	4
18	Hansi	1
19	Ghirai	5
20	Fatehabad	2
21	Bhatto Kalan	9
22	Adampur	3
23	Rajound	2
24	Safidon	4
25	Kalayat	4
26	Naultha	1
27	Jundla	1
28	Thanesar	1
29	Pundri	1

30	Narnaul	10
31	Rewari	2
32	Beri	3
33	Hassangarh	3
34	Meham	2
35	Kalanaur	3
36	Bhadurgarh	3
37	Badli	6
38	Salhawas	1
39	Rori	8
40	Dabwali	7
41	Darba Kalan	4
42	Ellanabad	5
43	Sirsa	1
43	Gohana	2
45	Rohat	1
46	Baroda	2
	Total	**174**

STATEMENT – B

District Ambala				**Rs. in Lakhs**	
Sr.	Name of Constituency	Sr.	Name of w/s Scheme	Estimated Cost	Expenditure incurred upto 1/79
1	2	3	4	5	6
1	Kalka	1	Jholuwal Group of 4 Nos. Villages	4.76	1.00
		2	Kiratpur Group of 3 Nos. Villages	5.24	1.35
		3	Asrewali	1.63	
		4	Pranpura	1.01	0.43
		5	Khera Sita Ram	1.36	0.30
		6	Rampur Sewri	2.48	0.30
		7	Bhairon Kisair	0.65	0.36
		8	Orian	0.45	0.61
		9	Pinjore	11.88	1.52
		10	Manaka	0.95	

		11	Ratpur Group of 2 Nos. Villages	3.37	2.00
		12	Khol Fateh Singh Group of 2 Nos. Villages	3.12	
		13	Ram Nagar Group of 8 Nos.	6.41	0.45
		14	Khuda Baksh Group. of 2 Nos. Villages	1.80	
		15	Gorak Nath Group of 7 Nos. Villages	7.93	0.25
		16	Bhagwan Group of 2 Nos. Villages	3.84	
		17	Bhagwan Group of 2 Nos. Villages	3.43	1.56
		18	Kami Group of 2 Nos. Villages	2.36	
		19	Malla Group	7.47	2.00

			of 4 Nos. Villages		
		20	Rajipur Jhajjra	5.63	1.95
		21	Bhawara Group of 3 Nos. Villages	7.08	0.79
			Total	**82.85**	**14.87**
2	Naraingarh	1	Bhood Group of 3 Nos. Villages	13.12	0.94
		2	Samanwa Group of 4 Nos. Villages	4.69	1.30
		3	Dhanana Group of 6 Nos. Villages	11.10	3.24
		4	Shahjanpur Group of 3 Nos. Villages	3.89	1.63
		5	Hangoli Group of 2 Nos. Villages	4.31	1.30
			Total	**37.11**	**8.41**

3	Yamunanagar	1	Nagal Group of 5 Nos. Villages	10.54	
4	Chhachhrauli	2	Taharpur Kalan Group of 22 Nos. Villages	20.19	
			Grand Total	**150.69**	**23.18**
District Bhiwani				**Rs. in Lakhs**	
1	Bawani Khera	1	Barsi	32.77	5.44
		2	Sumer Khera Group of 2 Nos. Villages	10.20	3.83
		3	Harita Group of 5 Nos. Villages	10.70	3.73
		4	Siwara	8.00	0.01
			Total	**61.67**	**13.01**
2	Mundhal	1	Talu Group of 2 Nos. Villages	11.50	6.01
		2	Mandhana	10.80	3.73
		3	Dhanana	18.78	2.84

		4	Badesra	7.20	2.55
		5	Un	6.13	
			Total	**54.41**	**15.13**
3	Dadri	1	Doki	5.22	2.55
		2	Patuwas Group of 8 Nos. Villages	34.0	0.13
		3	Atela Group of 8 Nos. Villages	15.72	0.04
			Total	**54.94**	**2.72**
4	Badhra	1	Tewala	2.50	2.55
		2	Badrai	2.82	0.03
		3	Chandeni Group of 3 Nos. Villages	7.80	0.05
		4	Lad Group of 4 Nos. Villages	13.32	0.03
			Total	**26.44**	**2.66**
5	Loharu	1	Sampura Group of 3 Nos. Villages	10.40	
		2	Digrota	1.50	

		3	Nagal Mala	1.15	
		4	Baeri Group of 2 Nos. Villages	3.25	
		5	Suretia Group of 4 Nos. Villages	4.08	
			Total	**20.38**	
			Grand Total	**217.84**	**3.52**
District Gurgaon				**Rs. in Lakhs**	
1	Gurgaon	1	Chandu Group of 3 Nos. Villages	9.85	0.10
		2	Gurgaon	8.32	0.06
		3	Jharsa Group of 2 Nos. Villages	14.76	0.79
		4	Garhi Hastu	2.96	
			Total	**35.89**	**0.95**
2	Sohna	1	Gham Raj Group of 3 Nos. Villages	4.33	1.94
		2	Silani Group of 2 Nos.	3.90	0.15

			Villages		
			Total	**8.23**	**2.09**
3	Hathin	1	Autha Group of 7 Nos. Villages	13.26	
		2	Madnaka Group of 8 Nos. Villages	13.08	0.30
			Total	**26.34**	**0.30**
4	Ferozepur	1	Basai Group of 2 Nos. Villages	4.22	
5	Nuh	1	Marora	3.80	
		2	Bajidpur Group of 17 Nos. Villages	33.48	0.58
			Total	**37.28**	**0.58**
			Grand Total	**146.32**	**8.37**
6	Taoru	1	Chhapera	2.96	
		2	Ulaita Group of 14 Nos. Villages	31.40	4.45

			Total	**34.36**	**4.45**
District Hissar				**Rs. in Lakhs**	
1	Narnaud	1	Haibatpur Group of 2 Nos. Villages	8.00	9.00
		2	Biana Khera	5.00	4.00
		3	Narnaud	13.62	7.42
		4	Bhadawar Group of 2 Nos. Villages	10.67	10.83
		5	Badahapper Group of 2 Nos. Villages	7.88	8.67
		6	Pali Group of 4 Nos. Villages	21.34	
		7	Kogsar Group of Villages	8.58	
		8	Puthi Saman	16.59	
		9	Kheri Gagan	7.73	
		10	Kani Kheri	6.66	
		11	Sisai Bala Group of 2	36.92	

			Nos. Villages		
			Total	**142.99**	**39.92**
2	Barwala	1	Kumbha Kheri	4.00	3.24
		2	Kothkalan Group of 2 Nos. Villages	18.00	
		3	Mutlauda Group of 3 Nos. Villages	25.79	
		4	Bhaini Amirpur Group of Villages	22.45	
			Total	**70.24**	**3.24**
3	Hansi	1	Umra Group of 2 Nos. Villages	20.84	
4	Ghirai	1	Naina Group of 3 Nos. Villages	26.94	
		2	Rajli	9.59	
		3	Kamri Group of 2 Nos. Villages	15.18	0.62

		4	Balak Group of 4 Nos. Villages	52.11	8.33
		5	Sisai Bala Group of 2 Nos. Villages	36.92	
			Total	**140.74**	**8.95**
5	Fatehabad	1	Dehman	7.29	0.55
		2	Tibbi Group of 6 Nos. Villages	16.23	
			Total	**23.52**	**0.55**
6	Bhattu Kalan	1	Kumhariyan	5.24	0.55
		2	Bhana Group of 4 Nos. Villages	32.61	2.09
		3	Banwali Group of 4 Nos. Villages	32.27	
		4	Khera Kheri	4.86	
		5	Bodi Khera Group of 2 Nos. Villages	13.89	
		6	Kheri Barki	5.72	

		7	Nagthela	17.43	
		8	Khasa Mahajan	6.80	
		9	Kulheri Group of 4 Nos. Villages	43.83	
			Total	**162.65**	**2.64**
7	Adampur	1	Muklan Group of 4 Nos. Villages	18.00	
		(a)	Mehalsera Group of 5 Nos. Villages	21.67	
		(b)	Kajla Group of 6 Nos. Villages	39.21	
			Total	**78.88**	**3.19**
			Grand Total	**639.86**	**55.30**
District Jind				**Rs. in Lakhs**	
1	Rajond	1	Alewa	9.65	
		2	Dhatrat	8.77	
			Total	**18.45**	
2	Safidon	1	Rajana Group	18.25	

			of 5 Nos. Villages		
		2	Kalwa Group of 2 Nos. Villages	18.56	
		3	Hat Group of 3 Nos. Villages	17.89	
		4	Dharauli Group of 3 Nos. Villages	16.49	
			Total	**71.19**	
3	Kalayat	1	Sajuma Group of 2 Nos. Villages	7.09	
		2	Kharak Pandwan	13.59	0.02
		3	Chhussla Group of 3 Nos. Villages	24.27	0.50
		4	Badsikri Kalan Group of 2 Nos. Villages	18.67	0.06
			Total	**63.62**	**0.58**

			Grand Total	**153.23**	**0.58**
District Karnal				**Rs. in Lakhs**	
1	Naultha	1	Shahpur Group of 4 Nos. Villages	20.26	3.91
2	Jundla	1	Nisang	2.56	0.36
			Grand Total	**22.82**	**4.27**
District Kurukshetra				**Rs. in Lakhs**	
1	Thanesar	1	Umri	3.92	0.78
2	Pundri	2	Pabnawa	3.85	0.75
			Grand Total	**7.77**	**1.53**
District Mohindergarh				**Rs. in Lakhs**	
1	Narnaul	1	Dochana Group of 2 Nos. Villages	3.50	2.33
		2	Tehla Group of 2 Nos. Villages	3.02	1.55
		3	Ghatesar Group of 2 Nos. Villages	5.49	0.02
		4	Niyamatpur	15.05	

			Group of 5 Nos. Villages		
		5	Naulaja Group of 4 Nos. Villages	10.80	
		6	Dholera Group of 2 Nos. Villages	8.65	
		7	Rambas Group of 5 Nos. Villages	15.77	
		8	Golwa	1.98	
		9	Amarpur	1.41	
		10	Dhancholi	1.27	
			Total	**66.94**	**3.90**
2	Rewari	1	Khatauli Group of 10 Nos. Villages	22.79	
		2	Nand Rampur Group of 5 Nos. Villages	11.55	
			Total	**34.34**	
			Grand Total	**101.28**	**3.90**

District Rohtak				**Rs. in Lakhs**	
1	Beri	1	Chimni Group of 2 Nos. Villages	9.77	2.25
		2	Gochhi Group of 2 Nos. Villages	11.65	
		3	Madana Group of 3 Nos. Villages	13.23	
			Total	**34.65**	**2.25**
2	Hassangarh	1	Bhambewa Group of 2 Nos. Villages	8.79	1.68
		2	Kurawar	15.89	
		3	More Kheri	7.31	
			Total	**31.99**	**1.68**
3	Meham	1	Farmana Group of 2 Nos. Villages	15.50	0.07
		2	Bansi Group of 5 Nos. Villages	28.16	1.04

			Total	**43.66**	**1.11**
4	Kalanur	1	Kahanaur	12.77	
		2	Khereri	4.36	
		3	Singhpura Group of 2 Nos. Villages	20.29	0.78
			Total	37.42	0.78
5	Bahadurgarh	1	Mandhoti	18.50	0.07
		2	Asoda Group of 4 Nos. Villages	35.54	
		3	Jasur Kheri Group of 2 Nos. Villages	20.53	1.50
			Total	**74.57**	**1.57**
6	Badli	1	Kharhar	12.00	0.06
		2	Badsa Group of 5 Nos. Villages	17.97	
		3	Nangla Group of 5 Nos. Villages	10.33	

		4	Sondhi Group of 4 Nos. Villages	9.17	
		5	Bhadana Group of 4 Nos. Villages	19.16	
		6	Barkatabad Group of 6 Nos. Villages	22.78	
			Total	**91.41**	**0.06**
7	Salahawas	1	Jhanswa Group of 3 Nos. Villages	12.51	
			Grand Total	**326.21**	**0.06**
District Sirsa				**Rs. in Lakhs**	
1	Rori	1	Khairian	6.63	4.14
		2	Kheowali Group of 4 Nos. Villages	11.00	11.25
		3	Bhadra Group of 3 Nos. Villages	15.55	0.96
		4	Rori	23.66	0.69

		5	Phagu	9.68	
		6	Kheowali Group of 6 Nos. Villages	23.96	
		7	Rasalia Khera Group of 5 Nos. Villages	26.55	
		8	Ratta Khera Group of 3 Nos. Villages	9.86	
			Total	**126.86**	**17.04**
2	Dabwali	1	Lohgarh Group of 2 Nos. Villages	6.40	0.10
		2	Abubshahar Group of 2 Nos. Villages	16.68	12.95
		3	Alika Group of 3 Nos. Villages	18.00	18.00
		4	Asakhera Group of 5 Nos. Villages	23.46	17.17
		5	Jagmalwali	9.54	
		6	Pipli Group of	19.35	

			5 Nos. Villages		
		7	Nillanwali Group of 4 Nos. Villages	19.90	
			Total	**113.33**	**48.22**
3	Derba Kalan	1	Pillimadori Group of 6 Nos. Villages	22.64	8.43
		2	Arniwali Group of 2 Nos. Villages	7.15	0.51
		3	Shahuwala	12.30	
		4	Gilla Khera Group of 4 Nos. Villages	18.60	0.50
			Total	**60.69**	**9.44**
4	Ellenabad	1	Bhurtwala Group of 5 Nos. Villages	21.18	
		2	Nathora Group of 5 Nos. Villages	28.77	
		3	Salankhera Group of 2	10.64	

			Nos. Villages		
		4	Haripura Group of 10 Nos. Villages	38.85	
		5	Ellenabad	14.58	0.96
			Total	**114.02**	**0.96**
5	Sirsa	1	Nazada Kalan Group of 6 Nos. Villages	29.89	
			Grand Total	**444.82**	**75.66**
District Sonepat				**Rs. in Lakhs**	
1	Gohana	1	Kheri Damkan Group of 4 Nos. Villages	18.35	0.01
		2	Gilaur Kalan Group of 2 Nos. Villages	9.46	
			Total	**27.81**	**0.01**
2	Rohat	1	Khanda Group of 3 Nos. Villages	12.86	0.02
3	Baroda	1	Jagsi	16.58	

		2	Nizapipura Group of 4 Nos. Villages	44.37	0.52
			Total	**60.95**	**0.52**
			Grand Total	**101.62**	**0.55**

Trades in the Industrial Training Institute for Girls at Jhajjar

***1064. Captain Mange Ram:** Will Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that training in a very limited number of trades is being imparted in the I.T.I. for Girls at Jhajjar, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to impart training in all the trades in the said Institute as is being imparted in teh Institutes at Rohtak and Dujana?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): There is no I.T.I. at Jhajjar or Dujana but a Government Industrial School for Girls at Jhajjar where training in two trades i.e. Cutting and Tailoring and Embroidery only, is imparted. However, there is at present no propsoal under consideration of Government to impart training in any additional trade in the said institute.

Thirty beds Hospital at Ellenabad

***1047. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 30 beds Hospital at Ellenabad, district Sirsa?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma): Not at present.

Minor from Dadri Feedar

***1013. Sh. Jai Narain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which the minor from Dadri Feeder in District Rohtak will be dug out/linked to the villages Gudan, Katesra and Kalanaur?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): The scheme of providing improved irrigation to area of villages Gudan, Katesra nd Kalanaur is under examination.

Free Board and Lodging to the Harijan Students

***1077. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether the Social Welfare Department, Haryana is considering any proposal to provide free board and lodging and free of cost books in the hostels to the students belonging to the Scheduled Castes; and

(b) whether the said department is considering to construct hostels in the rural areas in the State?

Revenue Minister (Sh. Preet Singh):

(a) No. However, a centrally sponsored scheme is being started before the end of this financial year for the benefit of children whose parents are engaged in scavenging of dry latrines or other unclean occupations i.e. tanning and flaying etc.

(b) No. However, aid under a Government of India's scheme is being given to institutions for setting up girls hostels.

Transfers of State Government Employees

***1095. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the transfer of employees of all cadres in the State continued even after the prescribed period; if so, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): जी हां। निर्धारित अवधि के प चात् स्थानान्तरण लोक सेवा की आव यकताओं तथा लोक हित को ध्यान में रख कर किये जा रहें हैं।

T.A./D.A. Drawn by each Minister

***877. Ch. Sant Kanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state the month wise total T.A./D.A. drawn by each Minister/Parliamentary Secretary, excluding the Chief Minister and Irrigation and Power Minister, during the period from 1-4-78 to 31-12-78 together with the expenditure incurred by the Government on account of their telephone charges, separately?

Chief Minister (Ch. Devi Lal): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure 'A').

Annexure 'A'

Statement showing the month wise total T.A./D.A. drawn by each Minister/Parliamentary Secretary excluding the Chief Minister and the Irrigation and Power Minister, during the period from 1-4-78 to 31-12-78, togetherwith the expenditure incurred on telephones.

Sr	Name of M/P Secr.	April, 78	May, 78	June, 78	July, 78	Aug, 78	Sept, 78	Oct, 78	Nov, 78	Dec, 78
		(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.	(a) TA/DA (b) Tel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
1	Sh. Mangal Sein, I.M.	(a)1581.00 (b)6965.90	(a) (b)7812.70	(a)1530.00 (b)2343.50	(a)2499.00 (b)8095.90	(a)1934.00 (b)12295.35	(a) (b)5588.50	(a)2932.25 (b)10793.45	(a)1656.00 (b)10667.70	(a)844.00 (b)3813.00
2	Sh. Ran Singh, AM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)437.00	(a)816.00 (b)3696.60	(a) (b)252.00	(a)1122.00 (b)368.00	(a)510.00 (b)5742.40	(a)1377.00 (b)107.00	(a)459.00 (b)154.50
3	Sh. Mool Chand	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

	Jain, FM	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
4	Sh. Bhajan Lal, CDM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)918.00 (b)2956.50	(a)1067.00 (b)1378.00	(a)714.00 (b)1107.00	(a) (b)6570.25
5	Sh. Prit Singh, RM	(a)561.00 (b)4789.00	(a)459.00 (b)982.25	(a)663.00 (b)1737.00	(a) (b)6158.45	(a)1173.00 (b)2111.50	(a)816.00 (b)2499.00	(a)561.00 (b)6426.20	(a)612.00 (b)1943.00	(a)561.00 (b)1378.50
6	Sh. Bir Singh, DM	(a) (b)	(a) (b)	(a)561.00 (b)107.00	(a)765.00 (b)361.50	(a)612.00 (b)3073.35	(a)663.00 (b)700.00	(a)816.00 (b)560.00	(a) (b)4608.60	(a)1530.00 (b)271.50
7	Lachhman Singh PWM	(a) (b)	(a) (b)	(a)306.00 (b)290.00	(a)765.00 (b)853.00	(a)714.00 (b)1160.60	(a)765.00 (b)3218.20	(a)816.00 (b)594.50	(a)714.00 (b)989.40	(a)612.00 (b)3362.10
8	Smt. Kamla Devi, HM	(a)561.00 (b)3144.70	(a)1307.00 (b)459.50	(a) (b)2560.20	(a)510.00 (b)4169.10	(a)561.00 (b)761.00	(a)1479.00 (b)2772.30	(a)624.75 (b)4661.75	(a)816.00 (b)726.00	(a)612.00 (b)2412.50
9	Sh. Ram Lal, IGM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)1988.50	(a)969.00 (b)3213.35	(a)816.00 (b)2496.90	(a)1914.50 (b)1246.00	(a)1803.00 (b)3984.70	(a)2393.75 (b)1841.60	(a)612.00 (b)2028.50
10	Hira Nand Arya, EM	(a)	(a)	(a)510.00	(a)561.00	(a)1816.00	(a)510.00	(a)612.00	(a)663.00	(a)612.00

		(b)	(b)	(b)360.00	(b)3370.00	(b)897.50	(b)3009.90	(b)3636.60	(b)990.50	(b)2670.00
11	Sh. Mehar Singh, J&CM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)510.00 (b)2472.90	(a) (b)2204.45	(a)1326.00 (b)699.00	(a)816.00 (b)438.50	(a)765.00 (b)1665.50
12	Sh. Sher Singh, ETM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)510.00 (b)100.00	(a)510.00 (b)1183.75	(a)816.00 (b)462.00	(a)612.00 (b)663.00	(a)612.00 (b)6214.60
13	Sh. Gajraj Nagar, FSM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)12.50	(a) (b)2487.40	(a)255.00 (b)	(a)1122.00 (b)332.00	(a)924.00 (b)652.50	(a)1505.00 (b)284.00	(a)906.00 (b)2044.55
14	Sh. Surinder Singh, CPS	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)1380.00	(a)1224.00 (b)1676.05	(a)408.00 (b)1137.00	(a) (b)1807.00	(a)1473.00 (b)6377.90	(a)561.00 (b)1596.00	(a) (b)1619.00
15	Sh. Baldev Tayal, Ex-Minister	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)112.00	(a) (b)1149.00	(a) (b)570.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
16	Sh. Ram Singh, Ex-	(a) (b)1771.40	(a)969.00 (b)1142.25	(a)510.00 (b)761.65	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

	Minister									
17	Sh. Tara Singh, Ex-Minister	(a)1224.00 (b)339.00	(a) (b)2797.70	(a) (b)400.25	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
18	Sh. Satbir Singh Malik, Ex-Minister	(a)561.00 (b)1979.60	(a) (b)3314.40	(a) (b)510.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
19	Smt. Sushma Swaraj, Ex-Minister	(a)625.00 (b)5673.00	(a) (b)167.50	(a) (b)2593.60	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
20	Sh. Jagan Nath, Ex-C.P.S.	(a) (b)880.00	(a) (b)147.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
21	Sh. Lal Singh, Ex Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)68.00	(a) (b)480.20	(a) (b)	(a) (b)	(a)1071.00 (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

22	Sh. Harsarup Bura, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)262.30	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
23	Sh. Sardar Khan, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)14.00	(a) (b)465.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
24	Sh. Mool Chand, Ex- Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)566.60	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
25	Sh. Bhale Ram, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)160.00	(a) (b)184.40	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
26	Sh. Bhag Mal, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)236.40	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

Note:- The above figures are based on the amounts actually drawn for payment in a particular month.

Scarcity of Drinking Water in Mewat Area

***906. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is a scarcity of drinking water in about 82% villages of Mewat area; and

(b) if so, the reasons for not giving priority to implement the drinking water supply schemes in the afore-said villages?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) उपरोक्त गांव को प्राथमिकता दी जा रही है।

Rural Industrialisation Programme

***1032. Sh. Shamsher Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of units registered under Rural Industrialisation programme in the State from 1st January to 31st December, 1979;

(b) the number of persons actualy employed/benefited under the said scheme during the above period;

(c) the amount of loan/subsidy advanced by the Government to such units during the above period;

(d) the number of large/medium industrial units registered in the State during the above period; and

(e) the amount of loan advanced/subsidy given to large and medium scale units by Government or other Government agencies during the above period?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

(a) 468 Units.

(b) 1286 Persons.

(c) Loan Rs. 378420/-

Subsity Rs. 9000/-

(d) 20 Industrial Units have been registered with D.G.T.D. from January, 1978 to December, 1978 in the large/medium scale sector.

(e) (i) Subsidy Nil.

(ii) Loan advanced Rs. 8724000/-.

स्वामी आदित्यवे I: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले दो दिनों से एम. एल.एज. होस्टल में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सदस्य पीकर बहुत अनाप भानाप बोलते हैं .....

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, अगर इस संबंध में कोई रैगुलर काल अटैन्शन मोशन हो तब तो ऐसी चीज आ सकती है।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई इस किस्म की बात है तो आप मेरे चैम्बर में मिलें, वहां मरै से डिस्कस करें या मेरे को आप लिखित रूप में कुछ दें जिसके ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा।

लाला बलवंत राय तायल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो हाउस की इलैक्टिड कमेटियां या नामिनेटिड कमेटियां हैं उनके चेयरमैन को नामिनेट आप करते हैं या लीडर आफ दि हाउस करते हैं ?

Mr. Speaker: This is no point of order. It is quie clearly laid down in the rules that the Chairmen of the Committees of the House are appointed by the Speaker. The Speaker appoints them.

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान एक विशेष बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कल हम कई एम.एल.एज. झज्जर गये थे। रास्ते में हमने रोहतक और हसनगढ़ हल्के के अन्दर देखा कि वहां पर बहुत ओले गिरे हैं .....

Mr. Speaker: It is a normal practice कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन कोई काल अटैन्शन मोशन आदि नहीं होता।

वर्श 1979–80 का बजट पे ा करना

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will present the Budget for the year 1979-80.

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 1979–81 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक स्थिति

बजट अनुमानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य को राज्य को अर्थ व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। हरियाणा राज्य वर्श 1977 की विना ाकारी बाढ़ों की तबाही से अभी मु कल से ही सम्भल पाया था कि इसे वर्श 1978 में फिर से बाढ़ों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। बाढ़ों के कारण राज्य के बहुत बड़े भागों में लोगों को असीम हानि तथा मुसीबतें सहनी पड़ीं। प्रभावित क्षेत्रों में कृशि उत्पादन को बड़ा धक्का पहुंचा और औद्योगिक उत्पादन भी रूक गया। सैंकड़ों परिवार बेघर और बेरोजगार हो गये। हरियाणा की सड़कों को बहुत अधिक क्षति पहुंची तथा सार्वजनिक उपयोग की कुछ अन्य संस्थाओं, जैसे ि ाक्षा संस्थाओं तथा हस्पतालों आदि, को भी नुक्सान हुआ।

इसके कारण राज्य के सीमित साधनों पर बहुत अधिक बोझ पड़ा तथा इस अदृश्ट स्थिति के कारण धन की जिन मद्दों पर खर्च करना था उधर से उसाक रूख मोड़ कर उसे इधर लगाना पड़ा।

तथापि इन बाढ़ों के बावूद, 1977–78 में हरियाणा का आर्थिक कार्यक्रम अनूठा रहा और इस वर्श राज्य में आर्थिक वृद्धि दर 7.9 प्रति ात थी जबकि राश्ट्रीय स्तर पर यह दर 7.4 प्रति ात रही। भाीघ्र लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 1960–91 के मूल्यों के आधार पर हरियाणा राज्य की आय 1976–77 में 559 करोड़ रूपये से बढ़कर 1977–78 में 603 करोड़ रूपये हो गई। परिणामस्वरूप स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1976–77 में 482 रूपये से बढ़कर 1977–78 में 508 रूपये हो गई। इस प्रकार एक वर्श में प्रति व्यक्ति आय में 26 रूपये की वृद्धि हुई है। 1976–77 में खाद्यान्न उत्पादन 52.50 लाख टन से बढ़ कर 1977–78 में 53.61 लाख टन हो गया। 1978–79 में 58.40 लाख टन उत्पादन की प्रत्या ाा है। यदि बाढ़ न आती तो उत्पादन और भी अधिक होता।

1977–78 के दौरान राज्य में औद्योगिक उत्पादन संतोशजनक रहा। इस अवधि के दौरान 37 आ ाय पत्रों/लाईसैंसों को जारी किया जाना ही हरियाणा में अधिक पूंजी लगाने की प्रवृति का सूचक हैं। वि ोशतः लघु, छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की उदार नीति से औद्योगिक निवे ा को बहुत प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात 1976–77 में 73.

12 करोड़ रूपये से थोड़ा सा बढ़ कर 1977–78 में 74.55 करोड़ रूपये हो गया। मार्च, 1977 में पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या, 18149 थी जो कि मार्च, 1978 में बढ़ कर 19325 हो गई। संगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार की संख्या 1978 में बढ़ कर 4.43 लाख हो गई जबकि मार्च, 1977 में यह संख्या 4.24 लाख थी। फिर भी हरियाणा के औद्योगिक संस्थानों में कुछ श्रमिक अ ाांति रही। वर्श के दौरान इन संथानों में 84 हड़ताले/तालाबन्दियां हुई जिनमें 11649 कामगारों ने भाग लिया। तथापि, राज्य समझौता म ाीनरी ने इन विवादों को भाांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में तत्परता से काम लिया। राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य विभागों का कार्य भी उत्साहजनक रहा, जिनका ब्यौरा मैं विभागीय गतिविधियों पर प्रका ा डालते हुए दूंगा। इससे पहले कि मैं आर्थिक स्थिति पर अपनी टिप्पणी समाप्त करूं मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा में कीमतें राश्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही रहीं। मुद्रा में वृद्धि हो जाने के बावजूद, कीमत लगभग स्थायी ही रहीं। उपभोक्ताओं के काम की वस्तुओं की सप्लाई सामान्यतः संतोशजनक रही। फिर भी, जिस वस्तु के अभाव के कारण कठिनाई पैदा हुई वह भी कोयले की कमी, जिसके कारण न केवल औद्योगिक उत्पादन में ही कमी आई बल्कि इसने ईंटें बनाने के काम को भी बुरी तरह प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई।

सातवां वित्त आयोग

भारत के राश्ट्रपति द्वारा गठित सातवें वित्त आयोग ने चालू वर्श के दौरान अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस आयोग ने (i) आय कर, (ii) केन्द्रीय उत्पाद भ्ाुल्क, (iii) सम्पदा भ्ाुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदान संबंधी निवल आय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच वितरण के संबंध में सिफारि ें की हैं। इसने राज्यों को ऋण राहत देने तथा राश्ट्रीय न ाबन्दी नीति लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाली हानि को पूरा करने के संबंध में भी सिफारि ें की हैं। वित्त आयोग ने करों के विभाज्य पूल में आय कर का हिस्सा 80 प्रति ात से बढ़ा कर 85 प्रति ात कर दिया है और केन्द्रीय उत्पाद भ्ाुल्कों में 20 प्रति ात के हिस्से को बढ़ा कर 40 प्रति ात कर दिया गया है। आयोग की इन सिफारि ाों के परिणामस्वरूप, जिन्हें भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, हमारे राज्य और अन्य राज्यों को पहले की अपेक्षा केन्द्र से अधिक धन रा ि ा प्राप्त होगी। न ाबन्दी लागू करने के कारण होने वाले घाटे के बारे में भारत सरकार इस हानि के केवल 50 प्रति ात अं रू ा को पूरा करने के लिए सहमत हुई है, जिसे वह वि ोश अनुदानों के रूप में देगी। आयोग की सिफारि ाों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला है कि हरियाणा राज्य को 1979–84 की अवधि के दौरान 38.29 करोड़ रूपये की ऋण राहत मिलेगी। वर्श 1979–80 के

बजट अनुमानों में सातवें वित्त आयोग की सिफारि ाों के परिणामस्वरूप केन्द्र से इस राज्य को प्राप्त धन रा ि ा भाामिल है।

लेखे 1977–78

वर्श 1977–78, महालेखाकार, हरियाणा द्वारा संकलित लेखों के अनुसार, 11.66 करोड़ रूपए के घाटे के साथ समाप्त हुआ। तथापि, वास्तव में वर्श 1977–78 की समाप्ति पर 0.36 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भोश था क्योंकि 31 मार्च, 1978 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास राज्य सरकार की 12.00 करोड़ रूपए की सरकारी हुंडियां थीं। वर्श 1977–78 के सं ाोधित अनुमानों द्वारा प्रत्या ि ात था कि वर्श 7.91 करोड़ रूपये के जमा भोश से समाप्त होगा। इसलिए वर्श के लेखों में सं ााधित अनुमानों की तुलना में 7.55 करोड़ रूपये की कमी का पता चला। यह कमी राज्य सरकार को मुख्यतः निम्नलिखित साधनों से होने वाली राजस्व आय में कमी के फलस्वरूप हुईः– (क) भू–राजस्व (0.96 करोड़ रूपए), (ख) बिक्री कर (2.32 करोड़ रूपए), (ग) माल तथा यात्रियों पर कर (0.50 करोड़ रूपए), (घ) बिजली भाुल्क (1.76 करोड़ रूपए), (ड) ब्याज/प्राप्तियां (0.70 करोड़ रूपए) (च) पुलिस विभाग द्वारा अन्य विभागों को दी सेवाओं के लिए प्राप्तियां (0.41 करोड़ रूपए), तथा (छ) सिंचाई प्राप्तियां (0.90 करोड़ रूपए)। आय में कमी इस कारण हुई कि राज्य के कुछ भाग में

भयंकर बाढ़ आ गई थी जिससे राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भारी दुश्प्रभाव पड़ा। फिर भी, उचित वितीय प्रबन्ध के फलस्वरूप, राज्य सरकार का आयोजना कार्यक्र (148.22 करोड़ रूपए) वर्श 1977–78 की वार्शिक योजना के 148.40 करोड़ रूपए के सं ाोधित पूंजीगत परिव्यय तक पहुंच गया था।

सं ाोधित अनुमान 1978–79

वर्श 1978–79 के बजट अनुमानों में यह मान लिया गया था कि वर्श 26.89 करोड़ रूपये के घाटे के भोश के साथ समाप्त होगा। सं ाोधित अनुमानों के अनुसार वर्श 14.13 करोड़ रूपए के घाटे के भोश के साथ समाप्त होने की संभावना है। चालू वर्श के बजट अनुमानों के सं ाोधन और 1979–80 के बजट अनुमानों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थिति उभरती है:–

		बजट अनुमान 1978–79	सं ाोधित अनुमान 1978–79	बजट अनुमान 1979–80
		(रूपए करोड़ों में)		
1	अथ भोश	(+)7.91	(+)0.36	(-)14.13

2	राजस्व लेखाः–			
	राजस्व प्राप्तियां	331.92	339.11	391.95
	राजस्व खर्च	278.20	294.40	328.97
	फालतू	(+)53.72	(+)44.71	(+)62.98
3	पूंजी लेखा (निवल)	94.27	83.55	94.46
4	सार्वजनिक ऋणः–			
	लिया गया ऋण	166.25	189.03	209.27
	ऋण की पुनर्अदायगी	144.28	144.11	176.88
	निवल	(+)21.97	(+)44.92	(+)32.39
5	ऋण/पे ागियांः–			
	पे ागियां	51.42	71.91	57.95
	वसूलियां	11.08	7.14	10.06
	निवल	(-)40.34	(-)64.77	(-)47.89
6	अन्तर्राज्यीयः–			
	समंजन	(-)1.36	(-)1.36	

7	सामान्य भविश्य निधिः–			
	अं ादान (निवल)	(+)8.15	(+)20.25	(+)12.60
8	जमा तथा पे ागियां			
	(निवल)	(+)17.33	(+)25.31	(+)11.54
	निवल परिणाम	(-)26.89	(-)14.13	(-)36.97

आदरणीय सदस्य देखेगें कि इस बात की सम्भावना है कि राज्य सरकार चालू वर्श के सं ाोधित अनुमानों में 12.76 करोड़ रूपये के भारी अंतर से वितीय स्थिति में सुधार कर ले। चालू वर्श के अथ ाेश के 7.55 करोड़ रूपये तक कम रह जाने के बावजूद यह सुधार महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुधार उल्लेखनीय हैः (क) बाढ़ों के दोबारा आने के कारण राहत उपायों, तकावी कर्जे तथा रासायनिक खादों के लिए उपदान देने के लिए 6.64 करोड़ रूपये का अधिक खर्च करना पड़ा, (ख) गन्ने की कीमत के लिए लगभग 1.75 करोड़ रूपये का उपदान दिया गया, (ग) सहकारी सैक्टर में चीनी मिलों को 3.00 करोड़ रूपये के कर्जे देने पडें ताकि वे गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया देय रा ि ा की आदयगी कर सकें, (घ) बजटोतर अवधि में पहली जनवरी, 1978 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत

अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो कि तें देने के कारण 3.25 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। चालू वर्श के सं ाोधित अनुमानों में इस अतिरिक्त खर्च के इलावा बाढ़ों के कारण अर्थ व्यवस्था में मन्दी होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राजस्व आय में कमी भी भाामिल की गई है। अनुत्पादी खर्च पर नियन्त्रण करके राज्य की अर्थ व्यवस्था में पुरूत्थान को बढ़ावा देने के लिए अपने नि चय तथा भरसक प्रयत्नों से तथा बाढ़ों से हुए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता से सरकार आय की कमी, सप्लाई तथा खपत को रोकने के लिए सक्षम हो गई है परन्तु ऐसा न करने पर स्थिति का सामना करना संभव नहीं हो सकता था यह हमारे लिए संतोश का विशय होना चाहिये।

बजट अनुमान 1979–80

अब मैं सदन के सम्मुख वर्श 1979–80 के बजट अनुमान रखना चाहता हूं। अच्छी आया होने के बावजूद, बजट अनुमान, 1979–80 में, वर्श के अन्त में 36.97 करोड़ रूपए का घाटा कल्पित किया गया है। 14.13 करोड़ रूपये के चालू वर्श के अन्त के घाटे के लिए भारत सरकार द्वारा पे ागी आर्थिक सहायता दिए जाने की सम्भावना है ताकि आगामी वित्त वर्श के दौरान हमारे प्रयत्न केवल 22.84 करोड़ रूपये के घाटे को पूरा

करने के लिए सीमित रहे। वित्त वर्श 1979–80 के लिए हमारी योजनागत अपेक्षाओं तथा इसके लिए उपलब्ध साधनों के बीच 22. 84 करोड़ रूपये के अन्तर को पूरा करने के लिए अर्थोपायों पर विचार करना आव यक होगा। मैं इस विशय का उल्लेख बाद में करूंगा।

वार्शिक योजना 1979–80

चालू वर्श पांचवीं योजना का अन्तिम वर्श है और 1978–83 की योजना का प्रथम वर्श भी है। चालू वर्श की सं ाोधित योजना 212.06 करोड़ रूपये की है जबकि वर्श 1979–80 की वार्शिक योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 227.30 करोड़ रूपये की रा ि ा अनुमोदित की गई है। वर्श 1979–80 की वार्शिक योजना में से खर्च का मुख्य भाग अर्थात् 171.36 करोड़ रूपये अथवा कुल योजना परिव्यय का लगभग 75.4 प्रति ात केवल कृशि, सिंचाई तथा बिजली सैक्टरों के लिये प्रस्तावित हैं। दूसरी ओर सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 29.80 करोड़ रूपये रखे गये हैं। चालू सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं और बाढ़ों की पुनरावृति को रोकने के लिए भाुरू किये गये निर्माण कार्यों की समाप्ति को राज्य की अर्थ व्यवस्था की विकास नीति में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटन का वर्णन योजना स्कीमों के

व्याख्यात्मक ज्ञापन में किया गया है। अब मैं विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उल्लेख करता हूं।

सिंचाई

यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा में प्रायः भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं परन्तु यहां कृशि फसलों की आव यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल कभी भी उपलब्ध नहीं होता। अतः यहां जल स्त्रोतों को बढ़ाने तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की आव यकता है। चालू वित्त वर्श में तथा आगामी वर्शों में सिंचाई परियोजनाओं को परमाग्रता देने का प्रस्तवा है। 1979–80 में, मुख्यत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों पर 58 करोड़ रूपए की रा ि। खर्च करने का प्रस्ताव है। इस रा ि। में पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक पर खर्च की जाने वाली 7.55 करोड़ रूपए की रा ि। भी भाामिल है। 1979–80 में लघु सिंचाई स्कीमों पर 1.00 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

रावी ब्यास के फालतू जल में से हरियाणा के हिस्से का जल लाने के लिए हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाले भाग में सतलुज यमुना योजक के निर्माण कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और यह निर्माण कार्य जून, 1979 तक पूरा हो जाना सम्भावित ह। इस कार्य के पूरा हो जाने पर वस्तुतः हरियाणा के अधिकां ा भू–पृश्ठ जल का उपयोग हो जाएगा तथा इसके प चात् वर्तमान सिंचाई

प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान देना आव यक हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, जिसमें वर्तमान जल मार्गों को पक्का करना भी सम्मिलित है, को परमाग्रता दी जा रही है। वि व बैंक के साथ एक करारनामें पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार हरियाणा में सिंचाई जल मार्गों को आधुनिक बनाने की परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जायेगी और 1978 से प्रारम्भ होने वाले 4 वर्शो के दौरान इस कार्य पर 58.60 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है चालू वर्श के 10.00 करोड़ रूपये के उपबन्ध को वर्श 1979–80 में बढ़ा कर 16.00 करोड़ रूपये कर देने का प्रस्ताव है।

प्रयोगात्मक आधार पर नहर प्रणाली पर एक सौ छिड़काव सेट लगाये जा रहे हैं ताकि ऊंचे तथा असमतल क्षेत्रों को वर्तमान सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा सके। इससे रिसन हानि कम हो जाने के कारण सिंचाई के लिए जल के प्रयोग में किफायत करने तथा उपलब्ध जल के साथ अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई के अधीन, लाने में किसानों की सहायता की जा सकेगी।

राज्य के सूखा सम्भावी क्षेत्रों में लोहारू और सेवानी उठान सिंचाई योजनाओं का कार्य संतोशजनक रूप से चल रहा है और इसे मार्च, 1980 तक मुकम्मल कर लिये जाने की संभावना हैं। वर्श 1979–80 के दौरान जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई योजना के लिए 12.50 करोड़ रूपये की रा ि ा की व्यवस्था की गई है।

लघु सिंचाई और नलकूप निगम राज्य के जल साधनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके प्रमुख क्रियाकलापों में गहरे नलकूप लगाना तथा जल मार्ग को पक्का करना भाामिल है। वर्श 1978–79 में 250 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 125 नलकूप लगाये जाने की संभावना है। वि व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत 173.35 लाख रूपये के अनुमानित परिव्यय से इस कार्यक्रम में 80 लनकूप भाामिल किए गए हैं। वर्श 1979–80 में निगम द्वारा 436 लाख रूपये के अनुमानित परिव्यय से 180 ावर्धन एवं सीधे सिंचाई नलकूप लगाने की योजना तैयार की जा रही है। इससे वर्श 1979–80 में 20000 हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। जहां तक वर्श 1978–79 में जल मार्गों को पक्का करने का सम्बन्ध है, 550.40 लाख रूपये के अनुमानित परिव्यय से 34.40 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जलमार्ग पक्के किए जाने की संभावना है। वर्श 1979–80 में निगम द्वारा 1923.10 लाख रूपये के अनुमानित परिव्यय से 120.10 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जल मार्गों को पक्का करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें वि व बैंक स्कीम के अन्तर्गत 86.10 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जल मार्गों को पक्का करना भी भाामिल है।

राज्य को वर्श 1977 तथा 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ों के बड़े पैमानों पर तबाही का सामना करना पड़ा। इन आपदाओं के दृश्टिगत बाढों के सम्बन्ध में व्यापक आधार पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसने विस्तृत विचार विम र्ा के

बाद 138.00 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से बृहत् बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास महायोजना की क्रियान्विति की सिफारि ा की। चालू वित्त वर्श के दौरान बाढ़ सहायता उपायों के लिए केन्द्र सरकार भी 9.00 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता देने के लिए सहमत हो गई। गत वर्शों में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास स्कीमों पर औसतन 2.00 करोड़ रूपये के वार्शिक व्यय के मुकाबले में चालू वित्त वर्श में ऐसी ही स्कीमों पर 18.82 करोड़ रूपये खर्च होंगे। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास स्कीमों पर खर्च वर्श 1979–80 में और बढ़ा कर 20.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास निर्माण कार्यों से रोहतक जिले के झज्जर, बहादुरगढ़, चुडानी तथा भूपानिया क्षेत्रों की तथा गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र की, जोकि बाढ़ों से अत्यन्त प्रभावित है, बाढ़ों से रक्षा हो जायेगी। जो निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं वे इस प्रकार है उजीना मोड़ नाला साहिबी पर मसानी बांध का निर्माण गांवों के गिर्द रिंग बांधों का निर्माण, वर्तमान नालों का निर्माण करना तथा उन्हें गहरा करना, इनमें नजफगढ़ नाला भाामिल है जिसकी क्षमता को 3000 से बढ़ाकर 10000 क्यूजेक रकने का निर्माण कार्य दिल्ली प्र ाासन द्वारा किया जाना है, तथा अलग थलग गढ़ों को मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ने के लिए योजक नालों का निर्माण। आ ाा है कि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप आगामी पांच वर्शों में राज्य का बाढों से काफी बचाव हो जायेगा।

यह निर्विरोध रूप से कहा जा सकता है कि हरियाणा राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा बाढ़ बचाव तथा बाढ़ सहायता का इतना व्यापक कार्यक्रम पहले कभी नहीं किया गया।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1983–84 के अन्त तक हरियाणा की अधिकतम मांग के 1304 मेगावाट तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। इस मांग को पूरा करने के लिए 2200 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अपेक्षित है इसके मुकाबले 1983–84 के अन्त तक राज्य में 1560 मेगावाट की क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है। इस प्रकार लगभग 640 मेगावाट की कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, बिजली उत्पादन स्कीमों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्श 1979–80 की आयोजना में, 62.24 करोड़ रूपए की कुल वार्शिक बिजली आयोजना में से 34.98 करोड़ रूपए की रा ि ा बिजली उत्पादन स्कीमों के लिए रखी गई हैं। 21.98 करोड़ रूपए की रा ि ा निम्नलिखित चालू स्कीमों के लिए रखी गई है:– ब्यास परियोजना यूनिट I, देहर, ब्यास यूनिट II, पौंग, देहर विस्तार, पौंग विस्तावर, 2x60 मेगावाट ताप बिजली घर, फरीदाबाद, 60 मेगावाट तीसरा यूनिट, फरीदाबाद, 2x110 मेगावाट ताप बिजली घर, पानीपत और 2x110 मेगावाट ताप बिजली घर, पानीपत II चरण। इसके अतिरिक्त, प ि चमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना, पानीपत में 2x110 मेगावाट वाला ताप बिजली घर चरण II तथा यमुनानगर में 4x200 मेगावाट वाला ताप बिजली घर जैसी राज्य में बिजली पैदा करने वाली नई स्कीमों के

लिए 13.00 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदे ा में सतलुज नदी पर 1020 मेगावाट तिबजली पैदा करने की क्षमता वाली नाथपा झाकरी परियोजना तथा जम्मू और का मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर 390 मेगावाट की दलहस्ती परियोजना नामक दो पन–बिजली परियोजनाओं का निर्माण भी भारत सरकार के राश्ट्रीय पन–बिजली परियोजना निगम द्वारा भाुरू किया जाना प्रस्तावित है और इन परियोजनाओं से हरियाणा राज्य के लिए अधिक से अधिक हिस्सा लेने की कोि ा ा की जा रही है। उत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदे ा में 600 मेगावाट वाली कोल बांध पन–बिजली परियोजना को भाुरू करने का प्रस्ताव भी है।

वर्श 1977–78 में देहर के स्थान पर 165 मेगावाट के दो सेट और ब्यास परियोजना पर पौंग के स्थान पर 120 मेगावाट के दो सेट चालू किए गए। देहर पर सेट सं. 3, नवम्बर, 1978 मे चालू किया गया और सम्भावना है कि सेट सं. 4, की म ीनें मार्च, 1979 तक काम करना भाुरू कर देंगी। पौंग का सेट सं. 3, अक्तूबर 1978 में और सेट नं. 4, मार्च, 1979 तक चालू किए जाने की संभावना है।

हरियाणा की ताप बिजली की स्थापित क्षमता 197.50 मेगावाट है। थर्मल प्राजैक्ट, पानीपत के पहले और दूसरे 2x110 मेगावाट के सेट 1979 के मध्य में चालू हो जाने की संभावना है। 60 मेगावाट थर्मल प्राजैक्ट का तीसरा यूनिट सितम्बर 1979 में

चालू हो जाने की संभावना है। इस प्रकार वर्श 1979 के अन्त तक ताप–बिजली की स्थापित क्षमता 477.50 मेगावाट तक और कुछ स्थापित क्षमता 1131.50 मेगावाट तक बढ़ जायेगी।

इस प्रकार पैदा की गई बिजली को खर्च करने के लिए पारेशण लाइनों का जाल बिछाने का प्रस्ताव है। इस उद्दे य के लिए 1979–80 के लिए 14.45 करोड़ रूपए की रा ि ा नि ि चत की गई है।

गांवों में बिजली लगाने और कृशक उपभोक्ताओं आदि को नये कनैक् ान देने जैसे सामान्य विकास कार्यों के लिए 12.11 करोड़ रूपये की रा ि ा रखी गई है। वर्श 1979–80 के दौरान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड लगभग 15000 नये नलकूपों को बिजली देने का विचार रखता है। इस प्रकार बोर्ड लगभग 44 लनकूपा कनैक् ान प्रतिदिन देगा। वि व बैंक की वितीय व्यवस्था से चल रही सिंचाई अधीन क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन गांवों को जल सप्लाई के लिए 1.20 करोड़ रूपये की लागकत से लघु सिंचाई नलकूप निगम के 385 आवर्धन नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव भी है। वर्श 1979–80 के दौरान 62780 अन्य अतिरिक्त कनैक् ान देने का भी प्रस्ताव है।

राज्य में 6731 गांवों मैं से 300 गांवों में पहले से ही सड़क रो ानी की व्यवस्था की जा चुकी है। यह सुविधा भोश गांवों को भी क्रमि कार्यक्रम में प्रदान करने का प्रस्ताव है। इनके

अन्तर्गत प्रति वर्श 500 गांवों को उक्त सुविधा जुटाने का ख्याल है।

इन विकासात्मक कार्यों से आगामी वित्त वर्श के दौरान बोर्ड की राजस्व प्राप्तियां 56.86 करोड़ रूपये से बढ़ कर 79.06 करोड़ रूपये हो जाने की प्रत्या ाा है।

यह देख कर खु ाी होती है कि किसानों की अमली कठिनाइयों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। उन्हें नलकूपों के लिए दिन के समय में बिजली कभी कभार ही दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, सप्लाई प्रतिदिन 8 घंटे तक सीमित थी। अब लगभग 22 घंटे प्रतिदिन बिजली की स्पलाई सुनि ित की गई है जिसमें आधी सप्लाई दिन के समय दी जाती है। अप्रैल, 1978 से पूर्व किसानों से बिजली का खर्च मीटरों की खपत के अनुसार वसूल किया जाता था। किसानों ने इस पद्धतिके विरूद्ध प्रतिवेदन किया। वर्श 1978–79 में किसानों की यह ि ाकायत दूर की गई और उन्हें विकल्प दिया गया है कि वे मीटर पद्धति या सामान्य दर पद्धति में से किसी एक को चुन लें। जिन किसानों ने सामान्य दर पद्धति को चुना था वे भी नलकूपों पर लगी अपनी कुट्टी म ाीनों को चलाने के लिए अलग से खपत में लाई गई बिजली के प्रभारों की छूट के लिए मांग कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देने में हर्श का अनुभव करता हूं कि आगामी वर्श से ऐसी कुट्टी म ाीनें समान दर प्रणाली में भाामिल की जायेंगी और ऐसे कार्यों के लिए उनसे अलग प्रभार वसूल नहीं किये जायेंगे।

हरियाणा के गठन के प चात् बिजली सप्लाई की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जून, 1977 में बिजली उत्पादन 66 लाख यूनिट प्रतिदिन तक बढ़ गया जबकि राज्य के गठन के समय यह 17 लाख यूनिट था। चालू वर्श में प्रतिदिन बिजली उत्पादन 85 लाख यूनिटों तक बढ़ गया है। इसी प्रकार स्थापित उत्पादन क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई है। जून, 1977 में, हरियाणा की स्थापित क्षमता 615.50 मेगावाट तक बढ़ गई जबकि नवम्बर 1966 में यह क्षमता 353.00 मेगावाट थी। चालू वर्श में स्थापित क्षमता 740 मेगावाट तक बढ़ गई है।

कृशि उत्पादन

राज्य के भीघ्र आर्थिक विकास में कृशिया का स्थान अत्याधिक महत्वपूर्ण है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रारम्भिक पिछडेपन के बावजूद हरियाणा ने हाल ही में कृशि क्षेत्र में प्रभाव ाली प्रगति की है। किसानों ने प्रायः कृशिया के वैज्ञानिक एवं आधुनिक ढंग अपना लिए हैं। उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाि ायों का प्रयोग क्रम ाः बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के कृशि उत्पादन में प्रभाव ाली वृद्धि हुई है।

हरियाणा में वर्श 1966–67 में 25.92 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन के मुकाबले वर्श 1976–77 में 52.50 लाख टन

खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वर्श 1978–79 में राज्य का लक्ष्य 58. 40 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन करने का है। इसमें से, 17.80 लाख टन का उत्पादन खरीफ में और 40.60 लाख मी0 टन का उत्पादन रबी में किया जाना था। अत्यधिक वर्शा से अभूतपूर्व बाढ़ें आई, जिसके परिणामस्वरूप बाजरा, मकई और जवार की खड़ी फसलों को भारी हानि पहुंची। इसे बावजूद, अनुमान है कि खरीफ में 17.80 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल का उत्पादन गत वर्शों के मुकाबले सबसे अधिक हुआ है और यह वर्श 1977–78 में 9.64 लाख टन के उत्पादन के मुकाबले वर्श 1978–79 में लगभग 12.50 लाख टन तक पहुंच गया है।

खरीफ के मौसम में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के 12670 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज 166.67 रूप्ये प्रति क्विंटल की इमदादी पर किसानों में बांटे गये थे, इमदादी रकम 27 रूपये प्रति क्विंटल थी, 6718 क्विंटल संकर बाजरे के बीज भी राज्य में बांटे गये थे। चालू रबी की मौसम में अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों के 51500 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज किसानों में बांटे गये हैं। इन बीजों पर इमदादी रकम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 75 रूपये प्रति क्विंटल तथा अन्य क्षेत्रों में 25 रूपये प्रति क्विंटल थी। चने के कुल 12500 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज 220 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर बांटे गये और इनमें इमदादी रकम 150 रूपये प्रति क्विंटल थी। चने की उपज बढ़ाने के लिए चने के लगभग

62500 राइजोबियम कल्चर भी इमदादी दरों पर बांटे गये थे। दिल्ली के चारों और 40 मील के घेरे में आने वाले गांवों की आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए सब्जी उत्पादन तथा मुर्गीपालन आदि के विकास का बृहत् कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

1978–79 के दौरान 2.00 करोड़ रूपये की रासायनिक खाद की सहायता दिये जाने की संभावना है तथा विभाग ने प्रयत्न किए हैं कि रासायनिक खादों की खपत अधिकाअधिक हो। 1979–80 के लिए रासायनिक खाद की खपत के लिए चालू वर्श के 2.40 लाख टन की तुलना में 2.80 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने पौधों के बचाव उपायों को भी तेज कर दिया है। कपास तथा तिलहन के क्रम ाः 31600 हैक्टेयर और 12672 हैक्टेयर क्षेत्र पर हवाई फुहार की गई।

वर्श 1979–80 के लिए 60 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निि चत किया गया है। चावल तथा गेहूं के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जायेगा।

हरियाणा में कृशि उत्पादन में वृद्धि का एक मुख्य कारण उथले नलकूपों द्वारा भूगत जल स्त्रोतों का संतुलित विकास है। अप्रैल, 1967 में उथले लघु सिंचाई यूनिटों और पंपिंग सैटों की संख्या 27957 थी जबकि अप्रैल, 1977 को यह संख्या बढ़ कर 221592 हो गई। 1978–79 के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर

240857 हो जाने की संभावना है और वर्श 1979–80 के अन्त में यह संख्या 2.53 लाख तक बढ़ जायेगी। लघु सिंचाई (नलकूप) की गति को बनाये रखने के लिए जुलाई, 1978 से आरमी करके 3 वर्श की अवधि के दौरान 20000 उथले नलकूप और 1800 पंपिंग सैट लगाने के लिए भूगत जल विकास स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। इन स्कीमों पर कुल 2413.50 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्श 1978–79 के दौरान कुल 282.00 लाख रूपये के खर्च पर 2460 उथले नलकूप और 75 पंपिंग सैट लगाये गये हैं।

वर्श 1978–79 में 3000 हैक्टेयर की वास्तविक उपलब्धि के मुकाबले में वर्श 1979–80 में मिट्टी तथा जल व्यवस्था उपायों के लिए 3500 हैक्टेयरका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्श 1979–80 में 96000 हैक्टेयर भूमि का भू–सर्वेक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्श 1979–80 में भू–सर्वेक्षण के लिए केन्द्र चालित स्कीम भाुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

लवणी तथा क्षारीय भूमि को सुधारने तथा भूमि को समतल करने की स्कीमों और वि ोश रूप से उठान सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई अधीन क्षेत्र की स्कीम को क्रियान्वित करने के उद्दे य से हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम को और सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्श 1978–79 के दौरान निगम ने 13400 एकड़ भूमि का सुधार किया है तथा 6010 एकड़ क्षेत्र पर भू समतलन का कार्य भी किया है। छोटे किसानों को जिप्सम पर 33.

5 प्रति ात तथा अन्य किसानों को 25 प्रति ात की रियायत दी जा रही है और वर्श 1979–80 के दौर भी इस स्कीम को चालू रखने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 71.39 लाख रूपये आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देने का उपबन्ध किया गया है।

कृशि विस्तार की बेनोर अथवा 'प्रि ाक्षण तथा निरीक्षण' प्रणाली का प्रचालन चालू वर्श की रोचक एवं नई बात है। इस योजना के द्वारा अनुसंधान वैज्ञानिकों/विशय वि ोशज्ञों से प्रौद्योगिकी के विस्तार कार्यकर्ताओं वि ाश्टतः आधार स्तर के कार्यकर्ताओं अर्थात् कृशि विकास अधिकारियों को, जो इस जानकारी को अन्ततः किसानों तक पहुंचायेंगे, अन्तरण में बहुत सुविधा होगी। एक कृशि विकास अधिकारी लगभग 700 किसान परिवारों का मार्ग द र्शन देगा।

प ाुपालन

हरियाणा में प ाुधन बहुत है और यह 'मुर्राह भैंस' और 'हरियाणा गाय' की वि व प्रसिद्ध नस्लों का घर समझा जाता है। हमने चयनात्मक प्रजनन द्वारा न केवल आने प ाुधन को सुरक्षित रखने और इसमें सुधार लाने का प्रयास किया है अपितु संकरण और कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा देसी प ाुओं के सुधार पर भी जोर दिया है।

प ाु प्रजनन के क्षेत्र में, भारत आस्ट्रेलियाई प ाु प्रजनन परियोजना, हिसार को आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता से हिम ीत भाुक्र बैंक से सज्जित किया जाएगा और इसके लिए भाीघ्र ही उपस्कर प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रकृश्ट प ाु विकास परियोजना अम्बाला, जींद, कुरूक्षेत्र और भिवानी, जिनका 1978–79 के दौरान एक प्रादे ि ा कृत्रिम सेचन केन्द्र और 15 प ाुपाल केन्द्र स्थापति करके विस्तार किया जा रहा है, अतिरिक्त प्रजनन सेवाओं और प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करेंगीं राजकीय प ाुधन फार्म, हिसार की मुर्राह भैंसों में से बूढ़ी और घटिया भैंसे निकाल कर उनके स्थान पर बढ़िया अधिक दूध देने वाली भैसें रख कर उसे बेहतर बनाया जाएगा।

मुर्गीपालन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किये जाने की गुंजाइ ा है क्योंकि दिल्ली हमारे राज्य के निकट है। देहाती ि ाक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करने और मुर्गीपालन उत्पादकता में वृद्धि करने के दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्श 1979–80 के दौरान 1000 मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अधीन बैंकों से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था भी की गई है कि इस योजना से लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रूपये की अधिकतक सीमा तक पूंजीगत निवे ा के 25 प्रति ात तक का सहायर्तानुदान दिया जाए।

अम्बाला जिला में मुर्गीपालकों के निकृश्ट पक्षियों तथा अण्डों को बाजार में बेचने के उद्दे य से अम्बाला में एक मुर्गीपालक संघ की स्थापना भी की जाएगी। वर्श 1979–80 में केन्द्रीय सहायता से वि ोश प ुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3605 परिवारों के लिए सहायक धन्धे उपलब्ध कराए जाने का उद्दे य है।

ऊन दर्जाबन्दी तथा विपणन केन्द्र, लोहारू ने वैज्ञानिक दर्जाबन्दी करने के प चात् ऊन उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त भेड़ पालने वाले लोगों को ऊन बेचने और उनके घरपर ही उन्हें बाजारी भाव पर उचित कीमत अदा करने में काफी सहायता की है। वर्श 1979–80 के दौरान ऊन की खरीद के लिए 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। यह केन्द्र इस ऊन का कोटि अंकन करेगा तथा बाद में इसे मिल मालिकों आदि को बेचेगा।

राज्य में प ुओं के रोगों का प्रभावी रूप से नियंत्रण करने तथा उनकी सेहत की रक्षा करने के लिए वर्श 1978–79 में 20 प ुचिकित्सा डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाने के अतिरिक्त 30 नई प ुचिकित्सा डिस्पेंसरियां स्थापित की गई हैं। वर्श 1979–80 में विभाग 20 डिस्पेंसरियों/प ुपालन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर नियमित प ु–चिकित्सा हस्पताल बनाने के इलावा लगभग 3 लाख रूपये के अनुमानित खर्च पर 20 नई प ु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलने की योजना बना रहा है।

डेरी विकास

कृशि प्रधान हरियाणा राज्य में डेरी उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की आय में लगभग 7.5 प्रति ात दूध तथा दूध निर्मित पदार्थों का अं ादान है। इसलिए डेरी उद्योग में महत्वपूर्ण अतिरिक्त उत्पादन न केवल राज्य में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए आव यक है अपितु ग्रामीणों की समृद्धि, उनके स्वास्थ्य और उनकी खु ाहाली के लिए भी जरूरी है।

11.00 बजे

विभाग ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें आरम्भ की हैं। वर्श 1979–80 में डेरी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 84.60 लाख रूपये का उपबंध किया गया है। वि ोश ग्रामीण रोजगार स्कीम के अंतर्गत वर्श 1979–80 में 1500 छोटी डेरी यूनिटों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 70.20 लाख रूपये की रा ि ा का उपबंध किया गया है।

हरियाणा डेरी विकसा निगम के चार दूध संयंत्र जींद, भिवानी, अम्बाला तथा रोहतक (प्रत्येक स्थान पर एक–एक) में चल रहे हैं। इन संयंत्रों की कुल प्रबन्ध क्षमता 185000 लिटर प्रतिदिन की है। इन संयंत्रों को दूध सप्लाई करने के लिए विभिन्न स्थानों

पर 7 अव ीतन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। 1978–79 में अव ीतन क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ाई जानी है। बल्लभगढ़ में स्थापित किया जाने वाला दूध संयंत्र भीघ्र ही चालू हो रहा है। यह संयंत्र प्रतिदिन 50000 लिटर दूध संभालेगा। मरू विकास कार्यक्रम के अधीन और दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आप्रे ान फ्लड का तकनीकी इनपुट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अधीन की गई विभिन्न कर्यावाहियों से दूध उत्पादन के बढ़ जाने की आ ाा है। भारतीय डेरी विकास निगम जून 1979 के आसपास 'आप्रे ान फ्लड' के दूसरे चरण को आरम्भ करेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत मरू विकास कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर हरियाणा के सभी जिलों को भाामिल किया जायेगा।

दूध की अधिप्राप्ति दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्याम से की जाती है। अब तक 1335 सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्श के पहले नौ महीनों में निगम के वीटा उत्पादन का विक्रय 532.56 लाख रूपये का हुआ है।

सहकारिता

हरियाणा मेें सहकारी संस्थाओं ने कृशि उत्पादन, स्वतः रोजगार, कृशि इनपुटों के वितरण, कृशि उत्पादन के विपणन, दूध के संग्रहण तथा विधायन, उपभोक्ता सामान की सप्लाई, कृशि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने औश्र सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की आर्थिक द ाा में सुधार लाने के क्षेत्र में महत्वपर्णू भूमिका आद की है।

हरियाणा में सहकारिता आन्दोलन ने जारे पकड़ा है ओर हाल ही के वर्शों में ऋण समितियों के सदस्यों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं। उधार लेने वालों को राहत देने के लिए 1–7–1978 से अल्पावधि कर्जों पर ब्याज की दर 14 प्रति ात से घटाकर 11 प्रति ात कर दी गई है। हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ ने कुछ कृशि आधारित परियोजनाएं बनाई हैं और अब दो बेलन संयन्त्रों तथा बिनौला विधयन संयन्त्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है। वर्श 1978–79 के लिए सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के वास्ते कुल 3.32 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है।

वि व बैंक ने 1.25 लाख टन की संग्रहण क्षमता वाले 1500 देहाती गोदामों के निर्माण में प्राथमिक सहकारी उधार एवं सेवा समितियों की सहायता करना मान लिया है। 2.14 लाख टन की संग्रहण क्षमता वाले 70 गोदामों के निर्माण में हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई एवं विपणन संघ को सहायता देने के लिए भी

वि व बैंक इतनी ही सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना पर 15.35 करोड़ रूपये की परिव्यय होगा।

कर्जो की उचित उपयोगिता सुनि चित करने और दुर्विनियोजन तथा गबन के अवसर कम करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।

पंचायतें

लगभग सता वर्श के प चात्, जून 1978 में हरियाणा में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव किये गये थे। सरपंचों तथा पंचों का सर्वसम्मति से चुनाव करने हेतु पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए 54.90 लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया है।

अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को समान आधार पर अनुदान देने के लिए 1.00 करोड़ रूपये की रा ि ा रखने का भी प्रस्ताव है।

वन

हरियाणा जैसे राज्य के लिए, जिसे राजस्थान की ओर से भयंकर रूप से बढ़ रहे मरूस्थल और बार–बार सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वन वि ोश रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः

उस राज्य की ओर बढ़ रहे मरूस्थल को रोकने के प्रयास में राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में भू–संरक्षण और वृक्ष रोपण के वि ोश प्रयास किए गए है।

1978–79 के दौरान कुल 164.80 लाख रूपये की लागत पर 5120 कतार किलोमीटर और 7915 हैक्टेयर में वर रोपण किए जाने की सम्भावना है। 1979–80 के दौरान विभाग की आयोजना है कि कुल 238 लाख रूपये की लागत पर 8925 कतार किलोमीटर और 9155 हैक्टेयर में वन रोपण किया जाए।

वार्शिक आयोजना 1979–80 में उपबन्धित सभी स्कीमें श्रम केन्द्रित हैं और उनका उद्दे य ग्रामीण बेरोजगारी और कम रोजगार वालों को रोजगार प्रदान करना है।

मछली पालन

हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही अन्य राज्य स्कीमों के माध्यम से मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा भ्रारू किये गये विस्तार कार्यक्रम पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देहाती लोगों में मछली पालन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। मछली पालन कार्यक्रम के सफल निश्पादन के लिए बढिया किस्म के डिम पोना की पर्याप्त संख्या होनी आव यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में डिम पोना उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। विभाग ने 12

डिम पोना केन्द्र स्थापित किये हैं और अब तक 25 लाख डिम पोना पैदा किये गये हैं। 40.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 1979–80 में 15 डिम पोना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

राज्य को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग पूरक परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। अतः राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास लाने के लिए साधन जुटाने की आव यकता है। वर्श 1978–79 में राज्य सरकार ने उद्योग के सभी क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया तथापि, ग्रामीण औद्योगिकरण तथा छोटे पैमाने के यूनिटों पर और अधिक बल दिया गया।

हमारी औद्योगिक नीति के केन्द्र बिन्दु ग्रामीण औद्योगीकरण के सराहनीय उद्दे य की पूर्ति के लिए उधार सुविधायें, तकनीकी मार्गद र्न, कच्चे माल की सप्लाई, विपणन सुविधायें तथा निर्मित स्थान आदि के रूप में सहायता देने के लिए एक विस्तृत स्कीम आरम्भ की गई ताकि गांवों में छोटे उद्यमकर्ता लघु? तथा छोटे यूनिट स्थापित कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्र में न केवल स्वतः रोजगार के अवसर पैदा हुए परन्तु इससे गांवों में समृद्धि की लहर भी दौड़ गई तथा उन ग्रामीण उद्यमकर्ताओं में एक नया वि वास भी उत्पन्न हुआ जिनकी योग्यता पहले प्रायः

सुप्त एवं अप्रयुक्त रही है। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्र ांसनीय श्रीगणे रूा किया गया। वर्श 1977–78 में 110 यूनिटों के लक्ष्य के मुकाबले में विभाग द्वारा 127 यूनिट स्थापित किये गये और आ ाा की जाती है कि चालू वित्त वर्श के अन्त तक इस स्कीम के अधीन 330 और यूनिट स्थापित कर दिए जाएंगे। इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए 15 मार्च, 1979 से एक वि ोश अभियान आरम्भ किया जा रहा है। भारत सरकार की नीति के अनुसार हरियाणा के सभी ग्यारह जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्दे य परियोजनाओं का अभिनिर्धारण, सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, कच्चे माल की सप्लाई करना तथा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि जैसी सभी प्रकार की सहायता एक स्थान पर जुटानी होगी।

और अधिक रोजगार अवसर, वि ोशतः देहाती क्षेत्रों में जुटाने के लिए राज्य सरकार ने देहाती क्षेत्रों में छोटे यूनिटों के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देने की घोशणा की है। इन प्रोत्साहनों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सम्भाव्यता रिपोर्टों की निः ाुल्क सप्लाई, सात वर्शों की अवधि के लिए बिजली भाुल्क से छूट, दो वर्शों की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट, 20 प्रति ात मूल्य अधिमान तथा कच्चे माल का 50 प्रति ात अतिरिक्त आबंटन भाामिल है।

उद्योग प्र ि ाक्षण विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह औद्योगिक

प्रि ाक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न इंजीनियरी तथा गैर इंजीनियरी व्यवसायों का प्रि ाक्षण दे रहा है। 1978–79 के दौरान दो नये उद्योग प्रि ाक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे।

हरियाणा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना में लाभकारी भूमिका अदा कर रहा है। चालू वित्त वर्श के दौरान फरवरी 1979 तक बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 74.00 लाख रूपये की रा ि ा वितरित की। वर्श 1979–80 में, बोर्ड इस प्रयोजन के लिए 190.00 लाख रूपये से अधिक रा ि ा वितरित करने की योजना बना रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्श होगा कि राज्य सरकार ने खादी आयोग तथा हरियाणा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त यूनिटों के निर्माण को और बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों को बिक्री कर की अदायगी से छूट देने का निर्णय लिया है।

हाल ही में सरकार के राजय उपक्रमों वि ोशतः सिक यूनिटों के कार्य को मुख्यतया सुचारू रूप से चलाने के विचार से वित्त विभाग (निवे ा–कक्ष) द्वारा उनका विस्तृत निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

सड़कें

सड़कें, अर्थ–व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है और कृशि तथा औद्योगिक प्रगति के उन्नयन में एवं अकाल तथा बाढ़ों जैसी आपात परिस्थितियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संतोश का विशय है कि राज्य में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई पर्याप्त बढ़ गई है। हरियाणा के गठन के समय 5100 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले केवल 1386 गांव पक्की सड़कों से जुडे हुए थे। हाल ही के वर्शों में सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रति हुई है और पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 16050 कि.मी. तक बढ़ गई है और 4550 गांव इनके अन्तर्गत आते हैं। राज्य सरकार ने 1982 तक प्रत्येक गांव के लिए पहुंच सड़की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्श के दौरान नयी सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर 9.50 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च की जा रही है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक 150 और गांवों के लिए 400 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली रोहतक सड़क के दिल्ली बहादुरगढ़ भाग और जी.टी. रोड के दिल्ली मूर्थल भाग को चार लने सड़कों में बदलने और पानीपत में उपमार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव भी भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे गए हैं।

इस वित्त वर्श के दौरान वर्शा जल के प्रति निकास तथा सिंचाई जल को नयी बनाई गई सड़कों के पार ले जाने के लिए दिसम्बर 1978 तक 556 नालों का निर्माण पूरा कर लिया गया। दिसम्बर 1978 तक लगभग 2300 कि.मी. लम्बी सड़कों को

चौड़ा भी किया गया तथा 770 कि.मी. सड़कों की सतह ठीक की गई।

राज्य में बड़े पुलों के निर्माण पर वि ोश ध्यान दिया गया है। जिन महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण हो रहा है, लगभग 41. 00 लाख रूपये की लागत का टांगरी नदी पर पुल, लगभग 3.00 करोड़ रूपये की लागत का यमुना नदी पर पलवल पुल, 68.00 लाख रूपये की लागत का अम्बाला भाहर में उपरिगामी पुल, 27.00 लाख रूपये की लागत का दिल्ली मथूरा सड़क को पार करता उजीना डाइव र्न ड्रेन वालापुल और 1.00 करोड़ रूपये की लागत का जी.टी. रोड़ पर भााहाबाद मारकंडा पुल।

वर्श 1979–80 के दौरान राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए 12.00 करोड रूपये की रा ि ा का उपबन्ध किया गया है। यह प्रत्या ि ात है कि 1979–80 में लगभग 550 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा जो 300 गांवों में जायेंगी।

सड़कों के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के भवनों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने दिल्ली के नहर विश्रामगृह को सुविधाजनक स्थिति और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप होने के कारण उसे किसान लॉज में बदलने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्श के दौरान हस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 129.00 लाख रूपये खर्च किये जा रहे हैं। चालू

वित्त वर्श के दौरान स्कूलों तथा कालिजों के भवनों के निर्माण पर 38.00 लाख रूपये की रकम खर्च की जा रही है।

करनाल के निकट मधुबन में स ास्त्र पुलिस मुख्यालय के परिसर का विस्तार किया गया है। फोरंजिक विज्ञान प्रयोग ाला तथा पुलिस प्र ि ाक्षण महाविद्यालय का निर्माण पहले ही हो चुका है। सफीदों, राई, सोनीपत, बवानी खेड़ा, बल्लभगढ़, जींद तथा साम्पला में पुलिस थानों के निर्माण का काम भ ारू हो चुका हैं। विभिन्न स्थानों पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत से रिहाय ाी मकान निर्माणधनी हैं। भिवानी में जिला जेल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बवानी खेड़ा का नया जेल भवन पूरा होने वाला है।

किसानों को विपणन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में मण्डियां निर्माणधीन हैं। इस उद्दे य के लिए चालू वित्त वर्श के दौरान 29.60 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की जा रही है।

परिवहन

वर्श 1978–79 के दौरान हरियाणा रोडवेज के परिचालन में पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक 2178 बसों की वर्तमान संख्या में 350 नई गाडियां बढ़ाने

का प्रस्ताव है। वर्श 1979–80 में 392 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इससे हरियाणा रोडवेज देहाती क्षेत्रों में अधिक बसें चला सकेगा। राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 6.00 लाख यात्रियों के लिए परिवहन सेवा प्रदान करती हैं और प्रतिदिन 5.00 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है।

वर्श 1979–80 में सिरसा, जींद, कनीना, पलवल तथा पुंडरी आदि में नए बस अड्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। यमुनानगर तथा सोनीपत में बस अड्डा तथा वर्क ाप केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर 100 बस क्यू भौल्टर बनाए गए हैं और वर्श 1979–80 में लगभग 150 अतिरिक्त बस क्यू भौल्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है। किफायत तथा कु ालता को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने गुड़गांव में लघु पैमाने पर बस बाडियां तैयार करने का काम भाुरू कर दिया है और आगामी वर्श में इन कार्यों को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है। किसानों को राहत देने के उद्दे य से कृशि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ट्रैक्टरों पर से 150 रूपये प्रति ट्रैक्टर वार्शिक के सांकेतिक कर की अदायगी से छूट दे दी गई है। मासिक पास वाले विद्यार्थियों को जनवरी, 1979 से किरायें में छूट दी गई है। सरकार ने हाल ही में भाारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

पंजाब मोटर दुर्घटना दावा नियमावली, 1964 के अन्तर्गत 10000 रूपये से अधिक के मुआवजा दावों के लिए निर्धारित न्यायालय भुल्क अधिक होने के कारण उन दुर्भाग्य ाली दावेदारों, जो कई बार निर्धन, विधवा अथवा अवयस्क होते हैं, को अत्याधिक हानि उठानी पड़ती हैं। इसलिये सरकार का प्रस्ताव है कि ऐसे दावेदारों की कठिनाई कम करने हेतू सम्बद्ध नियमावली में उपयुक्त संवैधानिक सं ाोधन किये जाएं ताकि 40000 रूपये तक के सभी दावों पर 10 रूपये की दर से न्यायालय भुल्क लागू हो सके।

पर्यटन

यह आ चर्य की बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मैंने आ चर्य इसलिए व्यक्त किया है, क्योंकि प्रकृति ने तो हमें दिया ही बहुत थोड़ा है जिसे हम पर्यटन विकास हेतु काम मे ला सकें। तथापि पर्यटन का मानचित्र देखने से यही स्पश्ट होाता है कि हरियाणा का पर्यटन कार्य वस्तुतः मानव निर्मित है और मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि ऐसा अं ातः हमारे राश्ट्र की राजधानी के समीप होने के कारण और अं ातः पर्यटन विकास में हमारी इच्छा ाक्ति तथा योग्यता के कारण हुआ है। पर्यटकों तथा स्थानीय ग्राहकों की आव यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में बनाये गये

अनेक पथ पा र्व केन्द्र और पर्यटन रेस्तरां इस क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। साधारण पर्यटकों के लिए अधिकां ाा केन्द्रों में सस्ते आवास स्थान की व्यवस्था की गई है। वर्श 1978–79 के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास पर 75.50 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। कुछ वर्तमान पर्यटन केन्द्रों में अतिरिक्त सेटों तथा रेस्तरां की व्यवस्था करने के अतिरिक्त सिरसा जिले के अबूब भाहर में नये पर्यटन केन्द्र का निर्माण हाल ही में भाुरू किया गया है। वर्श 1979–80 के लिए वर्तमान केन्द्रों में पर्यटकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने तथा सिरसा, कैथल, अम्बाला और रिवाड़ी में नये पर्यटन रेस्तरां खोलने के लिए 66.00 लाख रूपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

ि ाक्षा

ि ाक्षा विभाग, हरियाणा सभी स्कूल जाने योग्य बच्चों को भौक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने तथा वयस्कों में निरक्षरता के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस समय प्राइमरी में लगभग 11. 46 लाख, मिडल में 4.07 लाख तथा उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में एक लाख से भी अधिक विद्यार्थी हैं। कालिजों में दाखिले की संख्या में वृद्धि हुई है तथा इस समय राज्य में उच्चतर ि ाक्षा की विभिन्न संस्थाओं में 84000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 1979–80 के दौरान 6–11 वर्श के आयुवर्ग के 85000 बच्चों को

ि ाक्षा देने का प्रस्ताव है। अधिक बच्चों को ि ाक्षा की ओर आकर्शित करने तथा उन्हें स्कूलों में रखने के लिए 3973 प्राइमरी स्कूलों में मध्याह भोजन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत 4.22 लाख विद्यार्थी आते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न रूकावटों के बावजूद वर्श 1978–79 के दौरान 71 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडल स्कूल तथा 40 मिडल स्कूलों को उच्च स्कूल बना दिया है। वर्श 1979–80 में 90 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडल स्कूल तथा 90 मिडल स्कूलों को उच्च स्कूल बनाने का प्रस्ताव है। जरूरतमन्द विद्यार्थियों की आव यकता को पूरा करने के लिए सभी 7042 स्कूलों में बुक बैंकों की स्थापना भी की गई है।

महिलाओं, हरिजनों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों को ि ाक्षा देने के लिए 2 अक्तूबर, 1978 से एक राश्ट्रीय प्रौढ़ ि ाक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978–79 के अन्त तक राज्य में 3300 प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्र तथा 10+2+3 को लागू करने के लिए सभी सरकारी मिडल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान प्रयोग ाालाओं को 55. 00 लाख रूपये की लागत से सज्जित किया गया है। सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस प्रणाली को 1–4–79 से नौवीं कक्षा से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

विद्यालय ि ाक्षा में गणात्मक सुधार लाने के लिए सभी वर्गा के अध्यापकों के लिए एक भारी सेवारत प्र ि ाक्षण कार्यक्रम

चलाया गया था और इसे जारी रखा जा रहा है। 1978–79 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अधीन 32550 अध्यापकों को प्र ि ाक्षण दिये जाने की सम्भावना है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा नैतिक ि ाक्षा को लागू करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हरियाणा को दो वि वविद्यालयों के होने का सौभाग्य प्राप्त है – एक कुरूक्षेत्र में और दूसरा रोहतक में। इन वि वविद्यालयों की बढ़ती हुई आव यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्श के दौरान रोहतक वि वविद्यालय के लिए 150.00 लाख रूपये तथा कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के लिए 108.44 लाख रूपये की रा ि ा का उपबन्ध किया गया है तथा वर्श 1979–80 के लिए क्रम ाः 200.00 लाख रूपये तथा 141.44 लाख रूपये की रा ि ा का प्रस्ताव है। गैर–सरकारी कालिजों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्श के दौरान इन कालिजों के घाटे का 75 प्रति ात पूरा करने का निर्णय लिया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत पर वर्श 1978–79 में 20.50 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई है।

वर्तमान वि वविद्यालय अधिनियम (अधिनियमों) में गैर सरकारी कालिजों के प्राध्यापकों की सेवा सुरक्षा के संबंध में अपर्याप्त उपबन्ध के दृश्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कानून बनाया जाए।

सरकार ने वर्श 1973 से पूर्व तथा 1–1–1973 से 9–3–1973 तक की अवधि के दौरान तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए लगभग 11170 तदर्थ/वृतिक अध्यापकों/अध्यापिकाअें/सी एंड वी अध्यापको ंतथा जे.बी.टी. अध्यापकों की सेवाएं 1–1–1979 से नियमित कर दी हैं।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हरियाणा ि ाक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं में नकल करने की कुप्रवृति के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित वि ाश्ट उपाय किये गये हैं:–

(क) नकल करने की बुराई को रोकने के लिए 83 उड़न दस्तों की स्थापना।

(ख) परीक्षा केन्द्रों की आकस्मिक मंसूखी के सम्बन्ध में लोगों की गलत भांका दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षाओं के लिए आरक्षण केन्द्र बनाए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए 10.00 लाख रूपये का उपबन्ध किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूल ि ाक्षा के सुधार की ओर भी ध्यान दिया है। जिन गैर सरकारी स्कूलों को कुठारी आयोग के अधीन अनुदान दिया जाता था, वे वर्श 1974–75 से कोई अतिरिक्त वितीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे थे, यद्यपि उनके विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। राज्य सरकार ने अध्यापकों के वेतनों के लिए 3.00 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया है

ताकि ये गैर सरकारी स्कूल अपने अध्यापका/विद्यार्थी अनुपात में सुधार कर सकें। सरकार लड़कियों की ि ाक्षा को प्राथमिकता देने, कन्या विद्यालयों का दर्जा बढ़ान और उनके लिए नए स्कूल खोलने के लिए वचनबद्ध है।

खेलें

अनु ाासन तथा सहन ीलता के गुणों के विकास तथा राश्ट्रीय चरित्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका खेलें अदा करती है, उससे सरकार भली भांति परिचित है। खेलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए खेल–कूद विभाग, हरियाणा द्वारा अनेक स्कीमें बनाई गई है। इन सभी स्कीमों के लिए वर्श 1979–80 में 114.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालयों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति पर विभिन्न खेलों में प्र ि ाक्षण देने हेतु प्र ि ाक्षण ि ाविरों का आयोजन किया जा रहा है। चालू वर्श के दौरान, 33 प्र ि ाक्षण ि ाविरों का आयोजन किया गया था जिनमें 1275 खिलाड़ियों ने गहन प्र ि ाक्षण प्राप्त किया। खेल कूद विभाग द्वारा स्थापित मोती लाल नेहरू खेल कूद स्कूल, राई सोनीपत, एक अद्वितीय संस्था है। इस स्कूल में विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों को प्र ि ाक्षण देने पर वि ोश जोर दिया जा रहा है।

विभाग, प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक एक स्टेडियम स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। इस प्रयोजन

के लिए वर्श 1978–79 के दौरान 4.0 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा उत्कृश्ट तथा होनहार खिलाड़ियों को छात्रवृतियां दी जाती है।

हरियाणा में खेलों के विकास की पर्याप्त सम्भावना है। ग्रामीण खेल कूद केन्द्र स्थापित करने वाला यह पहला राज्य है। वर्श 1979–80 के अन्त तक ऐसे 374 केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है। सरकार ने उत्कृश्ट खिलाड़ियसों को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम भी भुरू की है और इस प्रयोजनार्थ वर्श 1978–79 के दौरान 2.58 लाख रूपये का उपबन्ध किया गया है। कु ती हरियाणा का अत्यधिक लोकप्रिय खेल है, उसे प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में जिला/खण्ड स्तरों पर कु ती केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अन्तर्राशट्रीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने नीचे दिये विवरण अनुसार पुरस्कार जीतेः–

क्रम.	नाम	खेल का नाम	जीता गया पुरस्कार
1	श्री महावीर सिंह	कु ती	अगस्त, 1978 में अलबूकर्क में आयोजित वि व स्कूली लड़कों की 49 किलोग्राम कु ती तथा अपने वजन की

			राश्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
2	श्री जयपाल सिंह	कु ती	उक्त खेलों में 32 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
3	श्री जय सिंह	कु ती	उक्त खेलों में 30 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
4	श्री सती ा कुमार	कु ती	उक्त खेलों में 36 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
5	श्री राजेन्द्र सिंह	कु ती	1. अगस्त, 1978 में एडमोंटन (कैनेडा) में राश्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
			2. 8वीं ए ियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता।
6	श्री सतबीर	कु ती	1. अगस्त, 1978 में एडमोंटन (कैनेडा) में राश्ट्रमंडल खेलों

	सिंह		में 57 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
7	श्री जगदी ा	कु ती	एडमोंटन (कैनेडा) में राश्ट्रमंडल खेलों में 68 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
8	श्री ई वर सिंह	कु ती	एडमोंटन (कैनेडा) में राश्ट्रमंडल खेलों में 100 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
9	श्री बहादुर सिंह	एथलैटिक	12/78 की बैंकाक में हुई 8वीं एि ायाई खेलों में गोला फैंकने में रजत पदक जीता।
10	कुमारी गीता जुत ी	एथलैटिक	उक्त एि ायाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 1500 मीटर की दौड में कांस्य पदक जीता।
11	श्री संत कुमार	एथलैटिक	1. उक्त एि ायाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में चौथा

			स्थान प्राप्त किया।
			2. 1500 मीटर की दौड़ में पांचवां स्थान प्राप्त किया।

इन उत्कृश्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने चालू वर्श में 57500 रूपये के नकद पुरस्कार दिये हैं।

स्वास्थ्य

वर्श 1978–79 के लिए 259.86 लाख रूपये के परिव्यय के मुकाबले में वर्श 1979–80 में 316.00 लाख रूपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है। विभाग क्रमिक रूप से प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक एक केन्द्र की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। बजट अनुमान 1979–80 में इस प्रयोजन के लिए 12.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। 1978–79 के दौरान 3 उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं जो उपचारात्मक तथा निवारक दोनों ही सेवाएं प्रदान करेंगे तथा एक ग्रामीण डिस्पेंसरी को उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्र में बदला गया है। 1978–83 की योजना अवधि के दौरान 133 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को भी उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव है। प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें उचित रूप से सज्जित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभाग कलानौर, नारनौंद, मुंढाल, बचनी, पाली, चौटाला, बालू तथा डिंग आदि में नए हस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहा है। हस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 148.00 लाख रूपये की रा ि ा की व्यवस्था की गई है। सिरसा में जिला टी.बी. सैंटर खोलने के प चात् सभी जिलों को राश्ट्रय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर लागू कर रही हैं। परिवा कल्याण कार्यक्रम को पीछे धक्का पहुंचा था। इसे पुनर्जीवित करने के लिए अनुस्थापन प्र ि ाक्षण ि ाविर आयोजित किए गए थे। दे ाी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत करने के लिए वर्श 1978–79 की राज्य की योजना में 32.85 लाख रूपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। आयुर्वेद औशध निर्माण तथा अनुसंधान कार्य के पर्यवेक्षण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा एक आयुर्वेद विकास बोर्ड का गठन किया गया है। चालू वर्श मं आयुर्वेदिक कालिज के निर्माण के लिए 16.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

स्नातकोतर चिकित्सा ि ाक्षा के क्षेत्र में छठी पंचवर्शीय योजना के दौरान मैडीकल कालिज, रोहतक में निम्नलिखित 5 नये पाठ्यक्रयों को भाामिल करने का प्रस्ताव है:–

1. एम.एस.सी. जीवरसायन

2. पी.एच.डी. औशधज्ञान एवं भारीर विज्ञान

3. एम.डी. मनोरेग विज्ञान

4. डी.एम. वृक्क ाास्त्र

5. एम.सी.एच. मूत्रविज्ञान

जी.टी. रोड पर बढ़ रही सड़क दुर्धटनाओं के ि ाकार व्यक्तियों की तकलीफों को कम करने के लिए जी.टी. रोड़ के साथ–साथ राजकीय हस्पतालों के हतातहत विभागों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं जल सप्लाई

हरियाणा के 6731 गांवों में से 4180 गांव कमी वाली क्षेत्रों में पड़ते हैं। 'राश्ट्रीय जल सप्लाई सफाई कार्यक्रम' के अधीन 31 मार्च, 1978 तक 1046 गांवों को जल सप्लाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। न्यूनतम 'आव यकता कार्यक्रम' के अधीन वर्श 1978–79 मे 4.5 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है तथा 'त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम' के अधीन भारत सरकार द्वारा 1.65 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। वर्श 1978–79 के दौरान 31 दिसम्बर, 1978 तक कमी वाले 55 गांवों को पीने के

पानी की सप्लाई सुविधाएं जुटाई गई हैं। आ ाा है कि चालू वर्श के अन्त तक 125 और गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। जल सप्लाई तथा वितरण केन्द्रों के भूदृ य निर्माण तथा रमणीयकरण का भी प्रस्ताव है।

वि व बैंक से सहायता प्राप्त 10.01 करोड़ रूपये की ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए परियोजना स्वीकृत हो चुकी है तथा चालू वर्श में इस कार्यान्वित करना भाुरू किया जा रहा है। 10.01 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय में से 2.00 करोड़ रूपये वर्श 1978–79 में तथा 2.50 करोड़ रूपये वर्श 1979–80 में खर्च किए जाएंगे। भोश रा ि ा दो अनुवर्ती वर्शों में खर्च की जाएगी। ग्रमीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए वर्श 1979–80 की वार्शिक योजना में 5.30 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है। वर्श 1979–80 के दौरान लगभग 190 गांवों में नलों द्वारा जल सप्लाई करने की व्यवस्था का प्रस्तवा है।

वर्श 1978–79 की वार्शिक योजना में भाहरी जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के लिए 1.00 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है। आ ाा की जाती है कि चालू वित वर्श के दौरान इस उपबन्धित रा ि ा से वर्तमान जल सप्लाई तथा मल–व्यवस्था स्कीमों के आवर्धन के अतिरिक्त एक नगर को आं ि ाक जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के आवर्धन के अतिरिक्त एक नगर को आं ि ाक जल सप्लाई तथा दो नगरों को मल व्यवस्था सुविधाएं जुटाई जाएंगी। वर्श 1979–80 में भाहरी

जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के लिए 1.20 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है।

आवास तथा भाहरी विकास

राज्य की जनसंख्या में वृद्धि से आवास की समस्या और अधिक विकट होती जा रही है। मकानों के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हरियाण आवास बोर्ड ने अब तक 5759 मकानों का निर्माण किया है तथा 4321 और मकानों का निर्माण भी विभिन्न अवस्थाओं में है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्श में 50.00 लाख रूपये तथा वर्श 1979–80 में 60.00 लाख रूपये खर्च किए जायेंगे।

आवास बोर्ड मकानों के निर्माण के लिए कर्जे भी दे रहा है। चालू वर्श के दौरान आरम्भ में 15.00 लाख रूपये की रा ि का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में जीवन बीमा निगम से इस स्कीम के अन्तर्गत वितरण करने हेतु धन उपलब्ध होने के बाद बढ़ा कर 60 लाख रूपये कर दिया गया और वर्श 1979–80 के लिए, इस प्रयोजनार्थ 21.00 लाख रूपये का सांकेतिक प्रावधान किया जा रहा है जिसे जीवन बीमा निगम से उपलब्ध रा ि तक बढ़ा दिया जायेगा। चालू वित्त वर्श में सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण कर्जे के रूप में 1300.00

लाख रूपये की रा ि ा वितरित की गई है और वर्श 1979–80 के लिए 100.00 लाख रूपये की रा ि ा का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

आवास बोर्ड हरियाणा ने फरीदाबाद में विभिन्न श्रेणियों के 1368 मकानों का निर्माण करने हेतु एक और स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर 155.64 लाख रूपये खर्च आने का अनुमान है। इस स्कीम के लिए आवास और भाहरी विकास निगम, नई दिल्ली 126.72 लाख रूपये का कर्ज देने के लिए सहमत हो गया है।

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग का उद्दे य भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का सुगठित और सुव्यवस्थित विकास करना है। इस प्रयोजन के लिए विभाग विकास योजनाएं तैयार करता है और गैर सरकारी उपनिवे ाकों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है तथा भूमि के उचित उपयोग एवं भाहरी विकास के लिए सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों को वि ोशज्ञ सहायता प्रदान करता है।

नगर सम्पदा विभाग भूमि का अभिग्रहण करता है और उसका सभी आधुनिक नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था सहित रिहाय ी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विकास करता है। भूमि का विकास 1977 में स्थापित हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वित्त वर्श में

5.00 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है और उसमें से 3.11 करोड़ रूपये उसके द्वारा पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण से खरीदे गए रिहाय ाी प्लाटों के लिए अदायगी आमतौर पर छः कि तों की बजाय दस कि तों में करने की सुविधा दी गई है।

रोजगार

रोजगार केन्द्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्श के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि 5.1 प्रति ात थी जबकि अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार यह केवल 2.5 प्रति ात थी। 30 सितम्बर, 1977 तक 4.3 लाख व्यक्तियों की नियुक्ति के मुकाबले में 30 सितम्बर, 1978 तक हरियाणा में संगठित क्षेत्र में लगभग 4.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ जिससे 4.6 प्रति ात की वृद्धि हुई। वर्श 1978 के दौरान हरियाणा के रोजगार केन्द्रों द्वारा 226000 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया और 36553 व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार प्रदान किया गया। हरियाणा में 1978–79 के अन्त तक रोजगार केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 43 हो जाने की सम्भावना है जबकि पिछले वर्श के अन्त तक इनकी संख्या 36 थी। भाारीरिक रूप से विकलांग

व्यक्तियों के लिए चण्डीगढ़ में वि ोश रोजगार केन्द्र की स्थापना की गई है।

चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी देने वाली नौकरियां प्रदान करना संभव नहीं है इसलिए विभाग ने लोगों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने का कार्य हाथ में लिया है। 1978 में विभाग 478 व्यक्तियों को स्वतः रोजगार दिलाने में सफल हुआ। वर्श 1978–79 के लिए 8 लाख रूपये का परिव्यय नियत किया गया है। चालू वित वर्श में अनुसूचित जातियों/कबीलों के लिए चंडीगढ में एक वि ोश रोजगार केन्द्र स्थापित किया जायेगा। चालू वित वर्श में पांच और ग्राम रोजगार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। महर्शि दयानन्द वि वविद्यालय, रोहतक में हाल ही में एक वि वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग द र्शन ब्यूरो स्थापित किया गया है। वर्श 1979–80 के लिए योजना परिव्यय 8.94 लाख रूपये है।

बेरोजगारी की समस्या

वि ोशतः ि ाक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या सदैव राज्य सरकार का ध्यान आकर्शित करती रही है। 31 दिसम्बर, 1978 को राज्य में 2.90 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। इस संख्या में रोजगार केन्द्रों में दर्ज 1.46 लाख ि ाक्षित बेरोजगार व्यक्ति भी भाामिल है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए

सरकार ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण उद्योगीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ि ाक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के निवे ा वाले लघु/छोटे उद्योग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। सरकार ऐसे यूनिट स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा अन्य आव यक साधान प्रदान करेगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिए 'कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम' भाुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी अनाज के रूप में दी जायेगी।

छठी पंचवर्शीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर जुटाने वाली श्रम–प्रधान परियोजनाओं/स्कीमों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके इलावा, अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के उद्दे य से कृशि उत्पादन के लिए मंडियों, ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों, सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई, कृशि विस्तार एवं गोदामों के निर्माण के विकास संबंधी वि व बैंक परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेगी। अनुमान है कि छठी पंचवर्शीय योजना के अंत तक लगभग 5.12 लाख लोगों के लिए पूर्णकालिक रोजगार के सीधे अवसर जुटाये जाएंगे।

श्रम कल्याण

वर्श 1978–79 के दौरान राज्य में कुछ औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालों/तालाबन्दियों के कारण औद्योगिक सम्बन्धों में कुछ गड़बड़ी रही। कामगारों के विवादों को निपटाने तथा सामान्य स्थिति लाने के लिए वि ोश कदम उठाये गये हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य में व्याप्त समूची स्थिति में अब स्पश्ट सुधार हुआ है, प्रमाणपत्र देने वाले सर्जन ने जिसे सामूहिक सूक्ष्म ऐक्स–रे उपकरण तथा प्रयोग ाला दी गई है, 5439 कामगारों का मैडिकल परीक्षण किया और व्यावसायिक तथा अन्य रोगों के 8 केसों का पता लगाया। कुछ अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी को न्यूनतम दरों में सं ाोधन कर दिया गया है और चालू वित वर्श के दौरान भोश महत्वपूर्ण अनुसूचित रोजगारों में अधिकां ा में मजदूरी की न्यूनतम दरों में सं ाोधन करने का भी प्रस्ताव है। महिला कामगारों के लाभ के लिए, विभाग राज्य के औद्योगिक नगरों में और अधिक ि ा ु गृहों की व्यवस्था कर रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

हरियाणा सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्म जातियों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देती है। उनके आर्थिक उत्थान और भौक्षणिक उन्नति के लिए विभिन्न स्कीमें भ्ारू की गई है। उनमें उल्लेखनीय स्कीमें ये हैं:

छात्रवृतियां देना, ि ाक्षण भाुल्क की प्रतिपूर्ति, कृशि भूमि की खरीद के लिए कर्जे देना, औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थानों में प्र ि ाक्षण के लिए छात्रवृतियां देना, मकानों, पेय जल, कुओं और चौपालों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना। वर्श 1978–79 के दौरान विभिन्न कल्याण स्कीमों पर 38 लाख रूपये खर्च किये जाने की संभावना है। हरिजनों के लिए चौपालें बनाने हेतु 5000 रूपये से 10000 रूपये प्रति चौपाल की दर से अनुदान के रूप में एक करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की साक्षरता और भौक्षणिक स्तर में सुधार के विचार से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी में वि ोश प्र ि ाक्षण देने के लिए 1979–80 की योजना अवधि के दौरान एक नयी स्कीम भाुरू करने का प्रस्ताव है। पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान, व्यावसायिक तथा रोजगार सम्बन्धी मार्गद र्ान देना, भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटान के लिए एक कक्ष की स्थापना करना, कुछ अन्य नयी स्कीमें हैं जो वर्श 1979–80 में क्रियान्वित की जाएंगी। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर वर्श 1979–80 में केन्द्र चालित स्कीमों पर खर्च किए जाने वाले 7.43 लाख रूपये के अतिरिक्त 163.05 लाख रूपये की रा ि ा और खर्च किए जाने की संभावना है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 9–2–79 से 2 प्रति ात से बढ़ाकर 5 प्रति ात कर दिया गया है।

राज्य सरकार के कल्याण संबंधी कार्यों को बढ़ाने में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने लाभदायक भूमिका निभाई है। अब तक निगम विभिन्न प्रकार की दस्तकारियां/व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3187 हरिजनों को 90.79 लाख रूपये के कर्जे वितरित कर चुका हैं। निगम ने कुछ औद्योगिक यूनिट भी स्थापित किये हैं ताकि हरिजनों को लाभप्रद रोजगार जुटाया जा सकें।

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण कार्यक्रमों को निश्पादित करने के लिए एक वि ाश्अ एजेंसी के रूप में काम करता है। विभाग ने कई स्कीमें बनाई तथा निश्पादित की हैं जिनका उद्दे य निराश्रित महिलाओं, उन पर निर्भर बच्चों, बूढ़ों तथा विकलांगों, भाारीरिक रूप से अपंगों, बाल अपराधियों, भिखारियों तथा विस्थापित लोगों का कल्याण करना हैं इससे पूर्व 150 रूपये तक की मासिक आय वाले भाारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को साकेत हस्पताल, चण्डी मन्दिर में कृत्रिम अंग निः ाुल्क दिए जाते थे। अब आय पर ध्यान दिए बिना भाारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्तियों को निः ाुल्क आवास, भोजन तथा कृत्रिम अंग देने का प्रस्ताव है। 'समजा कल्याण सैक्टर' में पांचवीं पंचवर्शीय के दौरान 28.37 लाख रूपये की रा ि ा नियत की गई थी, छठी पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श

कार्यक्रम सहित विभिन्न समाज कल्याण स्कीमों के लिए 401.56 लाख रूपये की रा ि ा का प्रस्ताव है। 'पोशण' के अधीन 69 लाख रूपये की रा ि ा नियत की गई है जिसमें से 30 लाख रूपये वार्शिक योजना 1979–80 के लिए प्रस्तावित है। अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श तथा अन्तर्राश्ट्रीय महिला द ाक के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग को महिलाओं तथा बच्चों की मांगें पूरी करने के लिए पुनर्गठित तथा पुनरभिस्थापित किया जायेगा। बाल विकास की विस्तृत स्कीमें भ ारू की जायेंगी। राज्य सरकार ने हरियाणा बाल कोश नाम से एक कोश स्थापित किया है जिससे जरूरतमनद बच्चों की सहायता की जायेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ रूपये की परिगामी निधि स्थापित की जायेगी। इस निधि में राज्य सरकार का अं ाद न 5 करोड़ रूपये होगा और बाकी 5 करोड़ रूपये जनता द्वारा अं ादान के रूप में दिये जाएंगे।

'धात्री–सेवा स्कीम' के अन्तर्गत लगभग 90 अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल की जा रही है। वि व बाल वर्श में इस स्कीम से लगभग 100 और बच्चों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

भाहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के कुपोशण की समस्या कम करने के लिए 19 भाहरों में एक वि ोश पोशण कार्यक्रम भ ारू किया गया है। राज्य में भिखावृति की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए पानीपत में भिखारियों के लिए एक प्रमाणित संस्थान खोला गया है।

वृद्धावस्था पेन ान योजना के अन्तर्गत 7729 पुरूश तथा महिलाएं 50 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से पेन ान प्राप्त कर रही है। वर्श 1979–80 में इस स्कीम से 8000 पेन ानरों को लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रूपये की रा ि ा रखी गई है।

कर वसूली एवं व्यापरियों की समस्याएं

बाढ़ों, श्रमिक वर्ग में अ ाांति तथा ि ाथिल औद्योगिक उत्पादन के परिणामस्वरूप राज्य की अर्थ व्यवस्था में जो हास आ गया था उसमें सुधार के चिन्ह दिखाई देते हैं। अप्रैल, 1978 में विभाग की राजस्व वसूली अप्रैल 1977 की वसूलियों से 7.75 प्रति ात कम थी। परन्तु दिसम्बर 1978 तक की वसूलियां गत वर्श की उसी अवधि की वसूलियों की तुलना में 8.65 प्रति ात बढ़ गई। दिसम्बर 1977 तक हुई 81.92 करोड़ रूपये की वसूली के मुकाबले में अप्रैल से दिसम्बर 1978 तक 89 करोड़ रूपये की वसूली हुई। वर्श 1978–79 के दौरान अनुमानित राजस्व की वसूली गत वर्श की वास्तविक वसूली के 119.62 करोड़ रूपये के मुकाबले में 128.05 करोड़ रूपये होगी। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में न ाबन्दी की नीति क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व में (अनुमानित 5.84 करोड़ रूपे) हानि होने पर भी 8.44 करोड़ रूपये की वृद्धि होने की आ ाा है। वर्श 1979–80 में राजस्व वसूलियों का बजट अनुमान 138.06 करोड़ रूपये है। वर्श

1979–80 के दौरान आबकारी राजस्व 2.00 करोड़ रूपये तक ओर कम हो जाने की सम्भावना है।

सरकार व्यापार तथा उद्योग की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और उनका समाधान करने के लिए वर्तमान कराधान कानूनों में कुछ सं ाोधन करने पर विचार किया जा रहा है। कर–प्रणाली को सुगम और युकित्युक्त बनाने के सम्बन्ध में सरकार को पराम र्ा देने के लिए विक्रय कर संरचना पुनर्विलोक समिति बनाई जा चुकी है।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रथम यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य व्यापारियों की करयोग्य प्रमात्रा को बढ़ाकर 40000 रूपये से 1 लाख रूपये तक, विनिमतिओं की 10000 रूपसे से 25000 रूपये तक ढाबों, होटलों, तन्दूरों, लोहों, हलवाइयों, बेकरियों तथा इसी तरह की अन्य ऐसी स्थापनाओं की, जहां कि भारतीय भोजन तथा चाय दी जाती है, 25000 रूपये से 40000 रूपये तक कर दिया जाए। कर देय प्रमात्रा में इस वृद्धि से लगभग एक हजार छोटे व्यापारियों को, जो इस समय हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत हैं, पंजीकरण तथा लेखों इत्यादि के संधरण आदि से राहत प्राप्त होगी। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बहुत से नए करदाताओं को भी राहता मिलेगी, जो अन्यथा पंजीकरणीय हो जाते यदि करयोग्य प्रमात्रा को वर्तमान सीमा तक ही बने रहने

दिया जाता। निःसन्देह इस सिफारि ा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप राजस्व में लगभग 14 लाख रूपये वार्शिक की हानि होगी। दूसरे, अनि चतता के परिणामस्वरूप व्यापारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बिक्री कर निर्धारण मामलों को भीघ्र निपटा दिया जाए। वर्तमान समय में हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को धारा 28 के अन्तर्गत एक निर्धारण प्राधिकारी की विवरणी की अवधि की समाप्ति के पांच वर्श की अवधि के अन्दर–अन्दर निर्धारण के लिए केवल एक नोटिस जारी करना होता है। इसके प चात् इन केसों के निपटान के लिए समय की कोई पाबन्दी नहीं है। पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा बिक्री कर के मामलों के भीघ्र निर्धारण की मांग संबंधी व्यापार तथा उद्योग की कठिनाइयों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्धारण सम्बन्धी सभी मामले तीन वर्श की अवधि के अन्दर–अन्दर अव य ही मुकम्मल कर लिए जाएं। इस उपाय से, अनि चतता को समाप्त करने तथा कर निर्धारण कार्यवाही को संक्षिप्त करने से कर अदा करने वालों को बहुत राहत मिलेगी।

न ाबन्दी

क्रमिक रूप से चार वर्शो की अवधि के अन्दर अन्दर राज्य में पूर्णतया न ाबन्दी लागू करना सरकार की घोशित नीति हैं जिला गुडगांव में तौडू के आस पास 144 गांवों में तथा सिरसा जिला में चौटाला के आसपास 8 मील के घेरे में पूर्णतया न ाबन्दी लागू की गई थी। वर्श के दौरान देसी भाराब अथवा भारत में तैयार की गई विदे ाी भाराब के लिए कोई भी नया लाइसेन्स नहीं दिया गया है। वर्श 1978–79 के लिए देसी भाराब का कोटा 58 लाख प्रूफ लिटर से कम करके 46.40 लाख प्रूफ लिटर कर दिया गया है। न ाबन्दी कार्यक्रम के प्रत्येक अनुवर्ती वर्श में देसी भाराब के कोटे में 20 प्रति ात की काटौती करने का प्रस्ताव है। सदन को यह जानकर खु ाी होगी कि देसी भाराब के ठेकों को बन्द करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा पारित समस्त 125 प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार करके लागू कर दिये गये हैं। वर्श 1978–79 में न ाबन्दी के दिनों की संख्या 15 से बढ़ाकर 79 कर दी गई है। सदन को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि निम्नलिखित और कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। (i) विदे ाी भाराब की दुकानों की संख्या 1–4–79 से 40 प्रति ात तक कम कर दी जायेगी और उनके ठेके भी नियत लाइसेन्स फीस पर अलॉट किए जाने की अपेक्षा नीलाम किए जायेंगे, (ii) भाराब पीने की बुराई से लोगों को रोकने के लिए तथा न ाबन्दी का प्रचार करने के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों की उच्चस्तरीय राज्य समिति बनाई जाएगी। राज्य का लोक सम्पर्क विभाग इसके लिए अपना पूर्ण सहयोग देना, (iii) नगरपालिका

सीमाओं के अन्तर्गत भी मुख्य सड़कों पर भाराब के ठेकों की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

भाराब की बिक्री में धीरे धीरे कमी आ जाने से राजस्व की हानि बढ़ती जायेगी। वर्श 1978–79 में इससे 5.84 करोड़ रूपये की हानि होने की संभावना है। इस हानि के कम से कम 50 प्रति ात की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है।

सरकारी कर्मचारी

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति उल्लेखनीय सत्यनिश्ठा, समर्पण तथा अनु ाासन का प्रद र्ान किया। पिछले दो वर्शों के दौरान विना ाकारी बाढ़ों में जिस लगन से इन कर्मचारियों ने काम किया वह सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन को यह जानकर खु ाी होगी कि वर्श 1978–79 के दौरान सरकार कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथा दूरव्यापी निर्णय लिए गए है। प्रथमतः सभी वर्गों के कर्मचारियों के विभिन्न वेतनमानों, मंहगाई भतों, तथा पेन् ान सहित अन्य प्रतिकर रियायतों और लाभों के वर्तमान ढांचे का विस्तृत पुनरीक्षण करने के लिए वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया हैं दूसरे, हरियाणा सरकार के उन सभी कर्मचारियों को 15 रूपये से 35 रूपये के बीच प्रति मास के हिसाब से तदर्थ राहत दिये जाने का फैसला किया गया है जो

पहली जनवरी, 1973 को सेवानिवृत हुए थे। यह राहत 1–3–1977 से दी गई है। बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि पेन् ानरों को उनकी पेन् ान की 5 प्रति ात की दर के हिसाब से क्रम ाः 1–4–1979 तथा 1–9–1979 से कम से कम 5 रूपये और अधिक से अधिक 25 रूपये प्रतिमास की दो और राहतें दी जाएं। सेवानिवृति के एक वर्श के अंदर पेन् ान को परिवर्तित कराने के लिए आवेदन करने वाले पेन् ानरों के लगभग सभी वर्गों को चिकित्सा परीक्षण कराने से छूट दी गई है। तीसरे, सरकार द्वारा निम्नलिखित पुरानी अथवा आग्रहपूर्ण मांगें मान ली गई हैं और न्याय प्रदान किया गया हैः–

(क) लोक निर्माण विभाग की विभिन्न भााखाओं के लगभग 25000 कार्यप्रभारी कमागारों के वेतनमानों को, जिन्हें 1962 से सं ाोधित नहीं किया गया था, सं ाोधित कर दिया गया है। राज्य में चतुर्थ श्रेणी के कामगारों में सबसे अधिक निर्धन कामगारों को प्रति वर्श 24 लाख रूपये का लाभ होगा। यह खेद की बात है कि कांग्रेस भाासन के दौरान इनकी ज्यादातर उचित मांगों को पूरा करने में किसी न किसी बहाने से दूरी की जाती रही।

(ख) सिविल प ा चिकित्सकों के वेतनमानों में किये गये पक्षपात को समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य के प ा चिकित्सकों को 111900 रूपये का लाभ होगा।

(ग) कालिज के भाारीरिक व्यायाम प्र ि ाक्षकों/पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों की सिफारि ा वि वविद्यालय अनुदान आयोग की इच्छा अनुसार कर दी गई है जिसके लिये राजकोश से लगभग 2 लाख रूपये का खर्च होगा।

(घ) राज्य के कृशि विकास अधिकारियों ने पंजाब तथा हिमाचल के कृशि विकास अधिकारियों के समान ही नहीं बल्कि उनसे बेहतर कार्य किया है। किन्तु उनके वेतनमान बहुत कम थे। इसकी वजह से उनमें भारी मनस्ताप हुआ। इस अन्याय को हाल ही में दूर कर दिया गया है। उन्हें प्रति वर्श 16 लाख रूपये तक का लाभ होगा।

(ड़) तहसील तथा जिला कल्याण अधिकारियों के वेतनमान भी सं ाोधित कर दिये गये हैं।

(च) पुलिस कर्मचारियों के वस्त्रों के लिए 165388 रूपये तक का वार्शिक भता बढ़ा दिया गया है। उन्हें वर्श 1968 में प्रचलित दरों पर ये वस्तुएं प्राप्त होती थीं जबकि उस समय से कीमतों में बहुत ही वृद्धि हो चुकी है।

बाढ़ राहत

बाढ़ों ने राजय के वि ाल क्षेत्रों में चालू वर्श के दौरान बहुत तबाही की। इन बाढ़ों का 1156288 लोगों और

707444 हैक्टेयर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। इस विपदा में लोगों की सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार ने रासायनिक खाद तकाबी, बीज तकावी, भवन मरम्मत अनुदानों, बीज उपदान, दवाइयों, पेय जल की सप्लाई, दूध का पाउडर वस्त्र तथा कम्बलों आदि के रूप में सहायता प्रदान की। इस सहायता क अतिरिक्त बैंकों को भी निर्दे ा दिये गये कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए ब्याज की रियायती दर पर कर्जे दिये जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाने के लिए हरियाणा राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम नामक केन्द्र चालित योजना भी भुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू वित वर्श में 20000 टन के कुल आबंटन के मुकाबले में 7000 टन गेहूं पहले ही दिया जा चुका है। वर्श 1979–80 के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से 100000 टन गेहूं के आबंटन के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त चालू वित वर्श में 2500 टन गेहूं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त राहत के तौर पर बांटा गया। संयुक्त राश्ट्र अन्तर्राश्ट्रीय बाल आपात निधि से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किए जाने के लिए 34000 बच्चों के लिए वस्त्र तथा 44000 सूती कम्बल दिए। वर्श 1978–79 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुननिर्माण के लिए बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों द्वारा कर्जा लेने के लिए वाणिज्यिक बैकों के पक्ष में निश्पादित बन्धक पत्रों और करारनामों के दस्तावेजों के संबंध में

भारतीय स्टाम्प अधिनियम और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा छोड़ दी गई है।

लोक सम्पर्क

लोक सम्पर्क विभाग सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह लोगों को सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से अवगत कराता है। विभाग लोगों के विभिन्न विचारों से सरकार को सूचित रखता है। प्रचार के उद्देश्य से राज्य की विकासात्मक गतिविधियों से लोगों को अवगत कराने हेतु विभाग विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों, जैसे– प्रैस, श्रव्य–दृश्य साधन, सार्वजनिक बैठकों, आकाशवाणी प्रसार, प्रकाशनों, कवि सम्मेलनों तथा नाटकों का प्रयोग करता है।

हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। हरियाणा सरकार के मान्य संवाददाता अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू दरों पर सरकारी विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। वे एक वर्श में 2000 किलोमीटर की दूरी तक हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना किराये के यात्रा करने की सुविधा के लिए भी हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, मान्य संवाददाता जिला तथा उपमंडल स्तरों की शिकायत समिति के सदस्यों के तौर पर नामित भी किये जा सकेंगे।

अनुमानित घाटे को पूरा करने के उपाय

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उपर्युक्त पैराग्राफों में राज्य की वर्तमान सामान्य वितीय स्थिति, वर्श 1979–80 के बजट अनुमान तथा विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण चालू तथा प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों का विवरण दिया है। वर्तमान सरकार के पास वर्श 1977–78 के लिए 148 करोड़ रूपये की पहले ही अनुमोदित वार्शिक आयोजना थी जिसमें वह पर्याप्त रा ि ा भी भाामिल है जो सतलुज यमुना योजक नहर के पंजाब भाग पर खर्च की जानी थी। इस सरकार को अभूतपूर्व बाढ़ों से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा फिर भी, जैसा कि इस अभिभाशण के आरम्भी में संकेत किया गया है, हमने 148.40 करोड़ रूपये खर्च किए। इससे अपने लोगों की भलाई के लिए विकासात्मक स्कीमों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी हमारा दृढ़ नि चय तथा क्षमता स्पश्ट लक्षित होती है। चालू वर्श के लिए सं ाोधित अनुमान आयोजना परिव्यय 212.06 करोड़ रूपये है जो गत वर्श के अंतिम आयोजना परिव्यय से 43 प्रति ात की वृद्धि द ार्ाता है। वर्तमान सरकार द्वारा इन विकासात्मक खर्चों में लाई गई अधिक प्रति ातता हमारे राज्य के इतिहास में अपूर्व है। हमने अपनी उपलब्धियों को समेकित करना है और वास्तव में हमने विकास की गति को आगे बढ़ाना है। आगामी वर्श का 227.30 करोड़ रूपये का अनुमोदित आयोजना परिव्यय हमारे उद्दे यों के

प्रति हमारे दृढ़ संकल्प तथा समर्पण का स्पश्ट सूचक है। परन्तु इस उद्दे य की प्राप्ति के लिए हमें वर्श 1979–80 के अनुमान अनुसार 22.84 करोड़ रूपये की बजट सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे वि वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य तथा हरियाणा के लोग विकास हेतु स्त्रोंतो की आव यकता को पूरी तरह समझेंगे तथा इन्हें जुटाने में सरकार को अपना सहयोग दैंगे।

मैं आयोजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के पराम र्ा से 1979–80 की वार्शिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाने के प चात् होने वाले महत्वपूर्ण विकास का भी उल्लेख करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है राश्ट्रीय विकास परिशद् ने कुछ केन्द्रीय सैक्टरों तथा केन्द्र चालित आयोजनागत स्कीमों को छोड़ने और कुछ अन्य स्कीमें राज्य आयोजना को अन्तरित करने का प्रस्ताव किया है जबकि केन्द्रीय सैक्टर में कुछ राश्ट्रीय तथा अन्तर्राज्जीय महत्व वाली कुछ स्कीमों को अभी भी रखा गया है। केन्द्रीय सैक्टर और केन्द्र चालित स्कीमों को छोड़ने या अन्तरित करने के परिणामस्वरूप 2000 करोड़ रूपये की रा ि। वर्तमान गैडगिल फार्मूला के अनुसार नहीं अपितु 'आय समंजित कुल जनसंख्या' पर आधारित नये फार्मूला के अनुसार 'फार्मूला राज्यों' में आबंटित की जाएगी। हम समझते हैं कि जहां हमें उन स्कीमों, जिनका पहले पूर्णतया अथवा अं ातः केन्द्रीय सरकार वित पोशण करती थी, राज्य निधियों में से निरन्तर क्रियान्वित करना

पड़ेगा, वहां 2000 करोड़ रूपये के नये निर्मित पूल में हमारा हिस्सा आगामी चार वर्शों में 50 करोड़ रूपये से घट कर 25 करोड़ रूपये रह जायेगा। इससे केन्द्रीय सरकार से हमें अन्यथा उपलब्ध होने वाले स्त्रोतों में 6 करोड़ रूपये वार्शिक कमी होती है। स्कीमें ऐसी है कि हम इन्हें बन्द भी नहीं कर सकते अतः हमने इन्हें पहले ही बजट में भाामिल कर लिया है परन्तु हमें 6 करोड़ रूपये के वार्शिक घाटे को अं ातः अपने प्रयत्नों और अं ातः योजना आयोग को अपने विवेकाधीन अनुदान में से अधिक रा ि ा देने पर सहमत करके पूरा करना होगा।

प्रत्या ि ात बजट घाटे के कम से कम पर्याप्त भाग को पूरा करने के लिए मैं निम्नलिखित नये करों का प्रस्तवा रखता हूं:–

(i) हलवाई की दुकान चलाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनकी वार्शिक कर देय रा ि ा 40000 रूपये से अधिक है, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कर अदा करना होगा। इस उपाय से उन सामान्य हलवाइयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो केवल आम आदमी की आव यकताओं को पूरा करते हैं। इस उपाय से प्रति वर्श 49 लाख रूपये की आय होने की संभावना है। (ाोर एवं विघ्न)

(ii) दूध के क्रय मूल्य पर कर लगाने का प्रस्ताव है जबकि इस दूध का प्रयोग दूध उत्पाद बनाने के लिए किया जाए

और ऐसे उत्पाद बनाने वालों द्वारा राज्य से बाहर स्थित अपनी भााखाओं अथवा कार्यालयों में अथवा राज्य से बाहर पारेशण आधार पर बिक्री के लिए भेजे जाएं। इस उपाय से राज्य में दूध अथवा दूध उत्पादों के उपभोग पर किसी प्रकार का प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है परन्तु इससे प्रतिवर्श लगभग 80 लाख रूपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

(iii) अप्रैल, 1976 में बसों के किरायों की पिछली वृद्धि के प चात् हरियाणा परिवहन की परिचालन लागत में ईंधन, तेल, स्नेहक, टायरों एवं ट्यूबों और पुंर्जो के मूल्यों में वृद्धि के कारण और अन्य बातों के साथ–साथ 1976–78 के दौरान कर्मचारियों को राहत की छः कि तें देने के फलस्वरूप मजदूरी बिल में बढ़ौतरी हो जाने के कारण पहले ही काफी वृद्धि हो चुकी थी। आगामी वर्श के लिए केन्द्रीय बजट के पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में बढ़ाये गये उत्पाद भाुल्क से परिचालन लागत और बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में यह आव यक है कि परिचालन की बढ़ी हुर्ठ लागत को पूरा किया जाये तथा कम से कम सीमांत अधि ोश जुटाया जाये ताकि राजय परिवहन विभाग जनता को निरन्तर कु ाल सेवाएं प्रदान करता रहे। अतः बस किराये में समान आधार पर 12.5 प्रति ात की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस उपास से 3.40 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वार्शिक आय होने की संभावना है। (ाोर एवं विघ्न)

(iv) अभिहस्तांतरण पत्रों, बन्धक पत्रों तथा पंजीकरणीय प्रलेखों पर लगाया जाने वाला वर्तमान स्टाम्प भाुल्क तथा पंजीकरण भाुल्क समान आधार पर 25 प्रति ात बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे 2.75 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वार्शिक आय होने की संभावना है।

(v) सूती धागे पर बिक्री कर की दर 1 प्रति ात से बढ़ा कर 2 प्रति ात करने का निर्णय लिया गया है ताकि इसे पड़ोसी राज्यों में लागू करके बराकर किया जा सके। इससे 9 लाख रूपये की अतिरिक्त वार्शिक आय होगी।

(vi) 6.25 एकड़ तक की जोतों को खरीफ 1978 से भूमि कर की अदायगी से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की वार्शिक आय में प्रायः लगभग 1.40 करोड़ रूपये की कमी हुई है। यह न्यायोचित ही होगा कि बड़े तथा अपेक्षाकृत सम्पन्न किसान राजस्व में हुई उस क्षति को कम से कम आंि ाक रूप से पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त अं ादान दें जोकि उनके उन किसान भाइयों को राहत देने के कारण हुई है जिनके पास थोड़ी–थोड़ी जमीनें हैं। इस प्रकार 6.25 एकड़ से अधिक सभी जोतों पर समान रूप से 33.5 प्रति ात की दर से अधिभार लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस उपाय से प्रतिवर्श 1.30 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

(इस समय प्रतिपक्ष के सदस्यण सर्वश्री राव बीरेन्द्र सिंह, भाम ोर सिंह, सुरजेवाला, राव दलीप सिंह, बीरेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पोहलू, इन्द्रजीत सिंह, नारायण सिंह और मांगेराम गुप्ता बजट को किसान विरोधी बताते हुए सदन से वाक–आउट कर गये)

(vii) सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च निरन्तर बढ़ता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के रख–रखाव का खर्च बहुत बढ़ा है। कुल मिलाकर सिंचाई परियोजनाएं घाटे में चल रही है। क्योंकि आबयाने और अन्य प्राप्तियों से हुई कुल आमदनी से इन परियोजनाओं पर हुई भारी निवे ाों तथा परिचालन खर्चों का ब्याज भी पूरा नहीं होता। बे ाक 1975–76 में खु ाहाली कर खत्म करने के साथ–साथ आबयाना बढ़ाया गया था, किन्तु सिंचाई परियोजनाओं से हुए निवल वितीय लाभों में कोई वि ोश सुधार नहीं हुआ। इस तरह राज्य के आर्थिक विकास, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ केवल सिंचाई सैक्टर के लिए कुल योजना के लगभग 60 प्रति ात का परिव्यय रखा गया है, के साधनों को जुटाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इन परियोजनाओं से अब तक हो रही आमदनी की तुलना में ज्यादा आमदनी होनी चाहिए। अतः खरीफ 1979 से आबयाने पर एक समान आधार पर 10 प्रति ात को दर से अधिभार लगाए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से वर्श

1979–80 के दौरान 40 लाख रूपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आ ाा है।

(viii) पंजाब लघु खनिज रियायत (हरियाणा प्रथम सं ाोधन) नियमावली, 1967 के अधीन इसकी पहली अनुसूची में भाामिल सभी लघु खनिजों पर लगाई जाने वाली रायल्टी की दरों में 50 प्रति ात की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, परन्तु गैर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाली ईंटें बनाने की मिट्टी, साधारण चिकनी मिट्टी तथा साधारण मिट्टी पर लगाई जाने वाली रायल्टी की दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस उपाय से 50 लाख रूपये प्रति वर्श की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। (ाोर एवं विघ्न)

(viiii) सीमेंट पर बिक्री कर को 7 प्रति ात से बढा कर 10 प्रति ात करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से प्रति वर्श लगभग 35 लाख रूपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। (ाोर एवं विघ्न)

..... में आने के बाद जनता सरकार ने खाद्यान्नों तथा अन्य कृशि उपज को वहां से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा नि चत रूप से सही दि ाा दि ाा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। परन्तु संघ क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री कर तथा मार्केट फीसर की दरें बहुत कम होने के कारण बिक्री कर तथा मार्केट फीस की चोरी के परिणामस्वरूप हमारे राज्य को इनकी बहुत हानि होती थी। हरियाणा की पड़ौसी

मण्डियों में भी व्यापार पर भारी असर पड़ा। उतर क्षेत्रीय परिशद की बैठक में दिल्ली प्र ाासन को बार–बार इस बात के लिए मनाने की कोि ा ा की गई कि वह बिक्री कर तथा मार्केट फीस की दरों को अपने पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दें। फिर भी दिल्ली प्र ाासन अपनी जिद पद अड़ा हुआ हैं क्योंकि ऐसा करने से दिल्ली के व्यापार को बहुत ही अनुचित लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय की 'उचंति' कुप्रथा चल पड़ी है।

चिरकाल से हरियाणा के सम्मुख करों की चोरी एक अन्य समस्या थी। अनेक उद्योगपतियों ने जिनके उद्योग हरियाणा में है, अपने मुख्य कार्यालय हरियाणा से बाहर वि ोशतः दिल्ली में रखे हुए हैं। उनकी फैक्टरियां हरियाणा में वस्तुओं का उत्पादन करती थी परन्तु उनकी वस्तुओं की बिक्री यहां नहीं दिखायी जाती थी। ये वस्तुएं दिल्ली को अन्तरित कर दी जाती थी और अब भी कर दी जाती है तथा वहां बेच दी जाती है क्योंकि दिल्ली में केन्द्रीय बिक्री कर की दर भी बहुत कम है। इस प्रकार हरियाणा को प्रतिवर्श केन्द्रीय बिक्र कर की करोड़ों रूपये की हानि होती है और आय कर में राज्य के हिस्से में होने वाली कमी इसके अतिरिक्त है। बार–बार किये गये प्रयासों के बावजूद ये उद्योगपति अपने कार्यालय हरियाणा में नहीं लाये हैं।

इस खतरनाक स्थिति के उपचार के लिए यह प्रस्ताव हे कि हरियाणा में विनिर्मित तथा सड़क द्वारा इसकी सीमाओं से बाहर ढोयी जाने वाली कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर एक नया कर

लगाया जाये। यह कर ढोयी गयी वस्तुओं के न केवल भार के आधार पर बल्कि उनके मूल्य अथवा भार आयतन के आधार पर भी प्रभार्य होगा तथा यह पंजाब यात्री तथा माल कर अधिनियम 1952 (जो हरियाणा में लागू है) के उपबन्धों के अधीन आजकल प्रभार्य माल कर के अतिरिक्त होगा। यह कर पहले से स्थापित सीमा चौकियों पर केवल तभी प्रभार्य होगा। जब हरियाणा में विनिर्मित वस्तुएं हमारी सीमाओं को पार करेंगी। इस सम्माननीय सदन में बाद में प्रस्तुत किये जाने वाले इस नये उपाय से हरियाणा राज्य के अन्दर माल ढोने वाले परिवाहक प्रभावित नहीं होंगे। आ ाा है कि इस उपाय से पहले बताये गये कारणों से सोनीपत, बहादुरगढ़ तथा सांपला की सीमावर्ती मंडियां से खाद्यान्नों का व्यापार बाहर जाने से रूक जायेगा। इसके अतिरिक्त इस उपाय से राज्य को पर्याप्त अतिरिक्त आय होगी।

मैं हरियाणा के सभी परिवाहकों, व्यापारियों तथा सामान्य जनता से अपील करूंगा कि इस नये उपाय को लागू करने में हमें सहयोग दें। इसकी सफलता के बाद हरियाणा राज्य कुछ अन्य करों के प्रभाव क्षेत्र को घटा सकेगा।

उपर्युक्त प्रस्तावित उपायों से वर्श 1979–80 के दौरान 10.08 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होगी। फिर भी 12.90 करोड़ रूपये का घाटा रह जाएगा, जिसमें बिक्री करदाताओं को दी गई 14 लाख रूपये की रहात भी भाामिल है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। तथापि, यह घाटा उतना कम हो जाएगा

जितनी आय हमें पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विस्तारपूर्वक दिए गए नए उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हो सकेंगी।

माननीय सदस्य इस बात को भली–भांति समझ सकेंगे कि वर्श 1979–80 के बजट अनुमान मुख्यतः किसानों तथा गरीब जनता के कल्याण के लिए विकास संभावनाओं की गति तेज करने के विचार से बनाए गए हैं। मैं इस गरिमायुक्त सदन को वि वास दिलाता हूं कि इस परम उद्दे य को प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जाएंगे। प्र ाासन के स्तर में सुधार लाने और अपव्यय रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में इस सरकार को माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सहायता तथा सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लक्ष्य अभी दूर है। सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय से पीड़ित जनता सहायता के लिए पुकार रही हैं। लगातार बेरोजगारी के परिणामस्वरूप युवावर्ग अ ाांत हो रहा है। ये चुनौतियां बहुत बड़ी है। किन्तु इस सरकार ने इन चुनौतियों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है। लोगों की आ ाओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजअ द्वारा नहीं दि ाा में अग्रसर होने का प्रयास कर रही है।

आभार प्रद र्ान

अपना भाशण समाप्त करने से पूर्व मैं वित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं और उन द्वारा किये गये परिश्रम की सराहना करता हूं जिसके कारण मैं नि चत तिथि पर बजट अनुमानों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सका हूं। मैं महालेखाकार, हरियाणा के प्रति भी उन द्वारा दी गई अमूल्य सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूं। बजट के मुद्रण से सहयोग देने के लिए मैं चण्ड़ीगढ़ प्र ाासन का भी धन्यवाद करता हूं।

अब मैं 1979–80 के बजट अनुमान माननीय सदस्यों के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द (तालियां)

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 8th of March, 1979.

11.53 Hours

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 8th March, 1979)